[Shri T. N. Singh.]

information about the person or persons who are involved in this. If the Government will care to go into this question I would welcome it. In any case I shall be obliged if within a short period the Government come out with some information that they are taking action in this and will set up an enquiry into this matter at an early date.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-15 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at quarter past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE.

श्री ओउम्प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आज मुझे ऐसे विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो उसकी समस्त प्रगतियों का आधार होता है। भारतवर्ष को आज 25 वर्ष स्वतंत्र हुये हो गये, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उसके लिए शिक्षा मंत्रालय को और शिक्षा मंत्री को दोष नहीं देता, बल्कि मैं पूरी सरकार को दोष देना चाहता हूं। उनकी योजना बनाने वालों को दोष देना चाहता हूं, जिन्होंने और मंत्रालयों को तो महत्व दिया है, परन्तु शिक्षा मंत्रालय को अधिक महत्व नही दिया। जब बजट बनता है तो शिक्षा मंत्रालय एक कोने में खड़ा रह जाता है बेकार लोगों की तरह और ऐसा लगता है कि मानो शिक्षा मंत्रालय ऐसा ही है कि उसमें कुछ काम स्वयं ही हो जायगा। शिक्षा को बजट में कोई महत्व नहीं दिया गया जबकि शिक्षा ही मूल आधार थी, इन तमाम योजनाओं की ओर यही कारण है कि आज सरकार के सामने सर्वत्र असफलतायें नजर आ रही हैं। इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा संस्थाओं की उपेक्षा की। आशा है कि अब सरकार इधर ध्यान देगी। इसमें टूटा-फूटा जो भी कार्य हुआ है, उसके आंकडे मैंने देखे। उनके देखने से ऐसा पता लगता है कि बहुत अधिक प्रगति हुई है। जहां 1961 में 49 विश्वविद्यालय थे, वहां अब 1971 में 93 हो गये हैं। जहां 1961 में कालेजों की संख्या 1,783 थी, अब वह बढ़ कर 3,604 हो गयी है। इसी प्रकार अध्यापकों की संख्या भी बढ़ी है। जो पहले प्रोफेसर्स 63,053 थे, अब '71 में 1,28,876 हो गये हैं, परन्तु जब यह देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ तो आश्चर्य हुआ और आज ही जो एक प्रश्न का उत्तर आया शिक्षा मंत्रालय की ओर से उसे देख कर मैं तो आश्चर्य में रह गया कि 1961 में जहां निरक्षरों की संख्या 33 करोड़ 30 लाख थी, वहां अब 1971 में सेंसस रिपोर्ट के अनुसार उनकी संख्या 38 करोड़ 60 लाख हो गयी है, यानी शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है और निरक्षरों की संख्या बढती जा रही है, यह एक आश्चर्य और खेद की बात है। फिर आंकड़ों में यह भी है कि जहां प्रगति हुई है उस के आंकड़े भी हैं। निरक्षरता दूर करने की दिशा में प्रगति हुई है। 1951

में निरीक्षरों का जो प्रतिशत था वह 16.67 था, 1961 में यह वह 24.02 रहा, अब 1971 में वह 29.34 रहा और इस दिशा में बढोत्तरी हुई है, 5 परसेंट से 8 परसेंट, यानी 1951 से 1961 तक 8 परसेंट की बढोत्तरी हुई और 1961 से 1971 में जहां पहले 24.02 परसेंट था अब वह 29.35 परसेंट हो गयी, वह भी प्रगति कर गये और निरक्षरता की दिशा में केवल 5 परसेंट की प्रगति हुई। आजादी के समय 76 परसेंट के करीब निरक्षरता थी, अब वह 71 परसेंट है, 5 परसेंट उसे आप दूर कर सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा का मूल लक्ष्य एक बात को मानता हूं। बडे-बड़े इंजीनियर्स, डाक्टर्स, फिलासफर्स पैदा करना ही मैं शिक्षा का ध्येय नहीं मानता। शिक्षा का ध्येय मैं मानता हूं कि वह इंसान बनाये। अगर शिक्षा इंसान को इंसान नहीं बनाती और उसे केवल डाक्टर बना दे और उसमें इंसानियत न हो तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहां संस्कृत मे आता है:

'सक्षरा विपरीता: राक्षसा भवन्तु'। अर्थात् अगर पढ़ा लिखा आदमी गलत रास्ते पर चला जाय तो वह राक्षस बन कर खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि आज देश में साक्षरता की दृष्टि से पढ़े लिखों की संख्या तो बहुत बढ गयी है, परन्तु उन में जो इंसानियत की मात्रा थी वह घटी और इतनी घटी कि वह शून्य से भी ज्यादा नीचे गिर गई और उसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी आदमी, डाक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो चाहे मिनिस्टर हो, अपने पद पर रहते हुये काम नही करता, अपनी ड्युटी के लिये ईमानदार नहीं है और यही कारण है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। जिसका नाम राष्ट्रीय चरित्र है वह बिलकुल गिर गया है। मैं आज की बात नही कहता। उपाध्यक्ष महोदय मैं 1966 ई० में इंगलैंड से पानी के जहाज से आ रहा था, अलेक्जड्रिया पर जब जहाज आ कर रुका तो जहाज के कप्तान ने सब पैसेंजर्स को बुला कर यह कहा कि अब यूरोप नहीं है, यूरोप खत्म हो गया है, यहां से मिडिल ईस्ट शुरु हो गया है, मिडिल ईस्ट से भारत तक अब आपको चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार मिलेगा और बेइमान आदमी मिलेंगे, इसलिये आप बाजार में जाओ तो सावधानी से खरीदारी की बात कीजियेगा। इतनी ठेस लगी मुझको, जब भारत का भी नाम साथ में जुडा तो हमने कहा कि भारत के प्रति इस प्रकार का विचार है। तो राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान करने में आपने और शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया ? यह मैं मानता हूं कि शिक्षा प्रान्तीय विषय है, किन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी हैं और यूनियन टैरिटरीज भी आपके पास है, आप आदर्श उपस्थित कर सकते थे परन्तु नही किया और आज सर्वत्र चरित्रहीनता का, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, झूठ और बेइमानी का बोलबाला है और इसका यह कारण है कि हमारी शिक्षा में चरित्र-निर्माण को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूगा, मेरा सुझाव है कि जब तक शिक्षा संस्थाओं मे नैतिक

[श्री ओउम्प्रकाश त्यागी]

शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया जायगा, मारल टीचिंग को अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से नहीं लागू किया जायगा, चरित्र-निर्माण को भी शिक्षा का अंग नहीं बनाया जायगा, तब तक राष्ट्रीय कैरेक्टर बनेगा नहीं और जब राष्ट्रीय चरित्र नहीं बनेगा तो कोई भी योजना सरकार की सफल हो सकेगी, इसमें मुझे संदेह लगता है।

दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं और वह है प्राइमरी शिक्षा की बात। पहले भारतवर्ष में क्या रहा, कितनी संख्या पढ़े लिखे लोगों की थी कितनी नहीं थी वह और बात है, लेकिन अगला भारत तो हम बना डाले, अगले भारत में तो पढ़े लिखे लोग हो जायं, हम तो मौत के मुंह में खेड़ हुये हैं, परन्तु जिन लोगों के हाथ में बागडोर देनी है वह तो पढ़ लिख कर खडे हो जायं लेकिन इन 25 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार मैं यह देख रहा हूं कि साक्षरता की दिशा में हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, जो आने वाली संतानें हैं, उनमें भी अपढ़ हैं, निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ी है, 8 करोड़ से अधिक की उनमें संख्या बढ़ी है। उसका मूल कारण क्या है कि पहले के निरक्षरों में नये निरक्षर बढे हैं। जो करोड़ों की संख्या संतानों में निरक्षरों की संख्या बढ़ी है उसका कारण क्या है। इसके दो मुख्य कारण हैं। यह देश शहरो का नहीं है, यहां पांच हजार शहर होंगे तो बाकी 7 लाख से ज्यादा गांव होंगे, जहां कि सड़के नहीं हैं, कुछ नहीं है और वहां पर कहीं प्राइमरी स्कूल है आपके पास। एक-एक स्कूल बना दिया है दो-दो मील के फासले पर, तीन-तीन मील के फासले पर। कहीं-कहीं स्कूल है और वह दो-दो या तीन-तीन मील के फासले पर हैं, तो पांच या छः साल का बच्चा वहां कैसे पढ़ने के लिए जायगा। आपने यह जानबूझ कर किया है कि इस गांव के बच्चे पढेंगे। इससे चुनाव में प्रभाव पड़ेगा और आपकी, कुर्सियां संकट में पड़ जायेंगी। आप जनता की निरक्षरता का लाभ उठा रहे हैं। जब तक हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं बन जाता, तब तक आप छः साल या पांच साल के बच्चे को स्कूल में नहीं ले जा सकेंगे। परन्तु आज देश की यह स्थिति नहीं है। और उसके साथ-साथ एक चीज़ और है कि जो बच्चा स्कूल में आता भी है उनमें से भी 50 फीसदी बच्चे पांचवीं या छठी तक नहीं रह पाते हैं, पहले दूसरे या तीसरे वर्ष में ही खिसक कर चले जाते हैं, वह नहीं पढ़ पाते। उसका मूल कारण है ग़रीबी। माता-पिता ग़रीब हैं, वे अपने काम धंधों में भी बच्चों की सहायता लेते हैं और उस सहायता लेने के लिए वे बच्चों को नहीं पढ़ाते।

दूसरी सामाजिक बीमारी भी है। आज ही जवाब दिया मंत्री महोदय ने और वह यह कि गरीबी के कारण भी बच्चे बहुत से स्कूल से हट जाते हैं। मैं मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं, मैं गांव का आदमी हूं और मैं जानता हूं कि उसका कारण क्या है मास्टरों में, अध्यापकों में अधिकांश सवर्ण लोग हैं जो कि, जो गरीब बच्चे हैं, हरिजनों के बच्चे हैं, उनको मारते हैं, तंग करते हैं, बेइज्जत करते हैं और ऐसा वातावरण स्कूल में बना देते हैं कि वे बेचारे तंग आकर स्कूल छोड़ देते हैं। आज अनुसूचित

जाति के लोगों में भी भावना है कि हमारे बच्चे बी० ए० पास हों, ग्रेजुएट हों, उनकी यह इच्छा नही कि उनके बच्चे उनके साथ काम करने जाएं। उनकी जो भी इच्छा हो, परन्तु स्कूलों में वह वातावरण मिल रहा है, जिसको छोड़ कर वे भागे जा रहे है। ग़रीबी भी एक कारण है, परन्तु यह भी इस प्रकार का एक कारण है जो मैंने बताया। यह मंत्री महोदय के हाथ की बात तो है नहीं, यह तो सरकार के हाथ की बात है और अगर सरकार को इस देश का कल्याण करना है तो प्राथमिक शिक्षा को केन्द्रीय विषय बना लेना चाहिए, तुरन्त यह भारत सरकार का केन्द्रीय विषय बन जाना चाहिए और युद्ध-स्तर पर, जिस प्रकार युद्ध की तैयारी के लिए हमारे मिनिस्टर भागे-भागे फिर रहे हैं कि ईरान हथियार पहुँच गए पाकिस्तान ने चाइना से आर्म्स ले लिए, यह ले लिया, वह ले लिया, तो जिस प्रकार हमारे डिफेन्स मिनिस्टर रशिया भागे-जा रहे हैं, तो उससे भी तीव्र गति से हमारे शिक्षा मंत्री देश के कोने-कोने में भागते फिरें और देखें स्कूल कहां बने है, कहां नहीं बने हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर एक बार हम शिक्षा के दृष्टिकोण से उठे, तैयार हो गए, तो संसार में हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नही रहेगा, हम तैयार हो जाएंगे। परन्तु शिक्षा को युद्ध-स्तर पर लेना होगा। और 6 से 11 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। जो माता-पिता न दे सके, उनको इसके लिए आर्थिक सहायता देनी पड़ी, तो वह भी दी जाए। उनके बच्चों को अगर दोपहर को भोजन नही मिलता है तो गवर्नमेन्ट की ओर से देना चाहिए। परन्तु आने वाली संतान को यह गवर्नमेन्ट कह सके कि अब देश में कोई बे-पढ़ा-लिखा नहीं रहेगा। इस देश में पहले जो बे-पढ़ा रहा सो रहा, लेकिन आगे इस प्रकार की स्थिति नहीं रहने दी जाएगी।

दूसरी समस्या है प्रौढ़ शिक्षा की। यह समस्या तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेन्ट ने जानबूझ कर हल नही की। शिक्षा डेमोक्रेसी का मूलाधार होती है। अगर वह सरकार प्रजातंत्र को स्वीकार न करती एक लोकतंत्र के स्थान पर राज-तंत्र स्थापित करती, फासिज्म और नाजिज्म लेकर चलती तो मैं कहता कोई चिंता की बात नहीं है; क्योंकि उसमें तो पढ़े और बे-पढ़े सब एक डंडे से हांके जाते हैं। परन्तु प्रजातंत्र को स्वीकार करने के पश्चात फिर देश में बे-पढ़ रहें और बे-पढ़ आदमी यह न जाने वोटिंग के मानी क्या हैं, वोट की कीमत क्या है, वह जाने नहीं प्रजातंत्र क्या है, तो फिर इस देश में डिमोक्रेमी एक ढ़ोंग है। आज यही हो रहा है, एक ड्रामा बनाया हुआ है, जनरल इलेक्शन्स आते हैं, वोटिंग होती है और उपसभापति महोदय, मैं जानता हूं, जाति के नाम पर, बिरादरी के आधार पर, ऊंच-नीच के नाम पर, वोटिंग होती है, बे-पढ़ आदमी आंख बंद करके वोट डाल देता है। पूछिए उनसे: भाई, कहां जा रहे हो? तो जवाब देगा: गऊ माता को वोट देने जा रहा हूं। वोट गऊ माता को दे रहे हो या पार्टी को यह भी उसको पता नहीं। उनके दिमाग में यह है कि गऊ माता को वोट नहीं देगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा और इसी अनढ़ता और निरक्षरता के खयाल से ही माननीय बहिन प्रधान मंत्री इन्दिरा गाधी ने, गौ-रक्षा विरोधी होने हुए भी गऊ का चुनाव चिह्न लिया, यह निरक्षरता के पक्ष में इसीलिए, क्योकि जब 1961 में 33 मिन लिय लोग बे-

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

पढ थे, अब 386 मिलियन क्यो हो गए ? बढ़ क्यों गई संख्या ?

उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय के ऊपर मेरा विश्वास है, बहुत लायक आदमी हैं और मै समझता हूं वे जवाब देगे तो योग्यता से जवाब देंगे, परन्तु मैं यह कहना चाहता हू कि जब देश यह निश्चय कर लेता है कि देश में निरक्षर आदमी कोई नही रहेगा, तो फिर क्यों आज ऐसी स्थिति है ? निरक्षरता 3 महीने मे दूर हो सकती है, चौथा महीना लगने की जरूरत नही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं चाइना का। चाइना ने अपने यहां सोच लिया था कि हमारे यहा निरक्षरता सरलता से तो दूर होनी नहीं। उन्होंने स्कूल और कालेजों को बंद कर दिया। विधार्थियों और अध्यापकों को आदेश दिया कि जितनी तुम्हारी डिग्रियां हो गई वह हो गई अब तुम जाओ देहात में। एक-एक गांव और चप्पा-चप्पा में चले जाइये और सब को साक्षर बना कर आइये। जब तक इस तरह की बात नही की जायेगी, तब तक हमारे देश में साक्षरता फैलने वाली नही है। हमारे यहां इतने कालेज है, इतनी यूनीवर्सिटियां है और इनमें से हजारों विद्यार्थी साक्षर हो कर निकलते है। इन लोगों का ग्रीष्म अवकाश होता है तो फिर इन लोगों का उपयोग चीन की भांति साक्षरता फैलाने के लिए क्यो नही किया जाता है।

शिक्षा मत्रालय हर साल रिपोर्ट निकालता है, आंकड़े देता है कि इस साल इतने स्कूल खोल दिये गये है और इतने बेकारों को नौकरी दे दी गई है। तो मेरा निवेदन यह है कि गर्मियों की छुट्टियां होती है, दो महीने की छुट्टी होती है, तो उसमें तमाम विद्यार्थियों को, प्रोफेसरों को और मास्टरों को साक्षरता फैलाने के काम पर लगाइये और उनकी मदद लीजिये। अगर आप एक दो अवकाशो में इस तरह का प्रयोग करेगे, तो सारे देश में बहुत काफी साक्षरता आ जायेगी, जिसके कारण काफी संख्या में लोग पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे और समाचारपत्र उनकी समझ में आने लगेंगे। लेकिन आजकल तो चुनाव की बीमारी है और यह एक ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी मे कोई भी आदमी जो उसमें प्रलोभन होता है, कुर्सी का प्रलोभन, वह उसको नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जो प्रौढ़ अशिक्षित है, वे साक्षर हो सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है।

मेरा सुझाव यह है कि आप ग्रीष्म अवकाश में मास्टरों का उपयोग करें और साथ में जो रिटायर्ड आदमी हैं उनकी सेवाओं को इस काम में लिया जाय। इस समय देश में जितनी भी शिक्षा संस्थाएं है, उनकी सेवा भी इस कार्य के लिए ली जाय।

दूसरी बात में ऊंची शिक्षा और कालेजों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यू०जी०सी० की ओर से इस तरह की संस्थाओं को सहायता दी जाती है। हमारी गवर्नमेंट धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है और वह जाति धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष की भावना से दूर है, परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई, जब मैंने कालेजों की वह लिस्ट देखी, जिनको सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। आज हमारे प्रान्तों में इस तरह की संस्थाएं हैं, जो जाति के नाम पर स्थापित हैं, जो धर्म के नाम पर स्थापित है और इस तरह की संस्थाओं

को सरकार की ओर से सहायता दी जा रही हे। मेरा कहना यह है कि कम से कम इस तरह की सस्थाओ को केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता नही दी जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस तरह की सहायता केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जाती है और मत्री जी यहा पर बतलाये कि यह सहायता किन किन सस्थाओ को कितनी कितनी दी जाती है क्योकि मैं इस सम्बन्ध मे आकडे देखकर आया हू। आपने काशी विद्यापीठ बनारस को, उसके अपने प्लान के लिए 3 लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 8 लाख रुपया दिया है। गुजरात विद्यापीठ को आपने दो लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 6 9 लाख रुपया दिया है। गुरुकुल कागडी को उसके प्लान के लिए आपने 1 लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 6 30 लाख रुपया दिया है। जामिया मिलिया को आपने 3 लाख रुपया दिया है और नान-प्लान्ड के लिए 28 लाख रुपया दिया है। किसी को आपने एक लाख रुपया दिया है तो किसी को 28 लाख रुपया दिया है। तो मै आप से यह जानना चाहता हू कि आप जो कालेजो को सहायता देते है उसका मापदड क्या है और किस आधार पर आप यह सहायता देते है? अगर आप पिछले आकडो को देखेगे तो आप को इस तरह की भिन्नता और भेदभाव दिखलाई देगा। मेरा कहना यह है कि आप सभी कालेजो तथा इस तरह की सस्थाओ को समान रूप से सहायता दे ताकि वे सब ऊचा उठने की कोशिश करे। अगर आप इस तरह की नीति पर चलेगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

उपसभापति जी, मुझे केन्द्रीय विश्वविद्यालयो के सम्बन्ध मे विशेष रूप से कहना है। केन्द्रीय विश्व-विद्यालयो की समस्या बहुत दिनो से चली आ रही है और जो भी शिक्षा मत्री साहसवाला, देशभक्त या ईमानदार आ जाता है, तो वह अधिक दिनो तक यहा पर नही रहता है और उसको यहा से छोडकर जाना पडता है। मुझे भय लग रहा है शायद वर्तमान मत्री श्री नूरुल हसन साहब—मेरी दृष्टि मे वे ईमानदार है और अच्छे आदमी है—भी रह सकेगे या नही क्योकि विश्व-विद्यालयो की समस्या सामने आई है। चाहिए तो यह था कि जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है उन सब पर एक ही नियमावली लागू होनी चाहिए थी, इस नियमावली के नीचे जो विश्वविद्यालय चलना चाहते है वे चले। साफ कहना चाहिए था कि हमारा देश सेक्युलर है, हम सेक्युलरिज्म मे विश्वास करते है, किसी भी ऐसे केन्द्रीय विश्व-विद्यालय को सहायता नही दी जायगी जिसका सेक्युलरिज्म मे विश्वास नही है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वह हिन्दू विश्वविद्यालय हो या अलीगढ मुस्लिम यूनीवर्सिटी हो। ऐसा नही हुआ। परिणाम यह हुआ कि अब अलीगढ यूनीवर्सिटी का बिल पास हुआ, उस पर प्रदर्शन हुए। इतना ही नही चूकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे है इसलिए केवल रूलिग पार्टी ही नही विरोधी पार्टीज भी बेचैन हो रही है मुसलमानो को खुश करने के लिए, कहती है कि तुम्हारे साथ बडा अन्याय हो रहा है, एजीटेशन करो, हम तुम्हारे साथ है, विरोधी पार्टियो की भी मीटिग हो रही है, उकसाया जा रहा है, सेक्युलर नीति के विपरीत भाषण और प्रचार चल रहा है, माननीय प्रधान मत्री जी के घर पर भी धरना दिया जा रहा है। मैं मत्री महोदय से आश्वासन चाहूगा कि इस प्रकार के आन्दोलन और प्रचार से आप लड़खड़ा तो नही

[श्री ओउम्प्रकाश त्यागी]

रहे, कही उसमे, अलीगढ यूनीवर्सिटी एक्ट मे परिवर्तन करने तो नही जा रहे, जैसी कि माग आ रही है और जो सेक्युलरिज्म के ढाचे मे फिट नही बैठती।

सस्कृति के बारे मे शिक्षा मत्रालय का एक काम सास्कृतिक प्रचार भी है। मैं पहले लोकसभा मे रहा और अब यहा भी हू, जितने मत्री आए उनसे मैंने बारबार जानने की चेष्टा की है, पूछा है कि भारतीय सस्कृति की परिभाषा क्या है? भारतीय सस्कृति क्या है, उसके सिद्धान्त क्या है कोई नही बताता। तमाम ससार मे एक देश भारत ही ऐसा है जिसकी सस्कृति नाम मे है पर उसकी सस्कृति क्या है यह कोई नही बताता। विद्वानो की दृष्टि से किसी भी देश की आत्मा उसकी सस्कृति होती है, सस्कृति के बिना राष्ट्र मर जाता है। भारत की सस्कृति क्या है–नाच और गाना। ये ललित कला को सस्कृति मान बैठे है और उसी के जगह जगह केन्द्र बन रहे है, नाच का केन्द्र बन जाता है, गाने का केन्द्र बन जाता है और जब बाहर सस्कृति के प्रचार के लिए प्रतिनिधि मडल भेजना होता है तो नाचने–गाने वालो का दल भेज दिया जाता है, वह चला जाता है और उसका प्रचार हो जाता है कि हमारे इतने सस्कृति प्रतिनिधिमडल चले गए और उन्होने उसका प्रचार किया, लेकिन आज तक किसी ने यह नही बताया–इतने विद्वान यहा से गए, अपनी सस्कृति का प्रचार करने के लिए–कि इन फडामेटल्स का प्रचार हमने किया। महात्मा गाधी अन्त तक हमारी सस्कृति का प्रचार करते करते मर गए। विदेशी विद्वानो ने भारतीय सस्कृति पर ग्रथ पर ग्रथ लिखे है, लेकिन हमको पता नही है कि हमारी सस्कृति क्या है। आज मैं माननीय मत्री महोदय से जानना चाहूगा कि वे बताए कि भारतीय सस्कृति के फडामेटल्स क्या है।

श्री बी० टी० केम्पराज . आप हो बता दीजिए।

श्री ओउम्प्रकाश त्यागी . मैं बताता हू।

एक माननीय सदस्य · किसको बता रहे हो।

श्री ओउम्प्रकाश त्यागी ऐसे आदमियो को बता रहा हू जो समझ नही रहे। अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। शौच, सन्तोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने सास्कृतिक प्रचार के लिए क्या किया? आपकी रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमे एक साहित्य अकादमी है। मैंने सोचा कि इसने कुछ किताबे लिखी होगी। उसमे नावल और ड्रामा भरे पडे है। तो सास्कृतिक प्रचार नावल और ड्रामा भी हो सकता है, लेकिन मैं यह जानना चाहूगा कि पहले तो आप यह बताये कि हमारी सस्कृति क्या है, इसके फडामेटल्स क्या है। इसके प्रचार के लिए आपने क्या किया है। मैं स्कूल मे बच्चो को देखकर आपसे पूछता हू कि वह बच्चे जानना चाहते है कि हमारी सस्कृति क्या है। आपने इसके लिए क्या साहित्य तैयार किया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि किसी देश का अभिमान और गौरव उसकी प्राचीन सस्कृति और इतिहास पर होता है। क्या भारतवर्ष का प्राचीन सास्कृतिक इतिहास नही है? भारतीय सस्कृति

का इतिहास नहीं है जिसके चिन्ह आज बेबीलोनिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया में मिलते है? तमाम दुनिया के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति पर ग्रन्थ लिखे हैं। लेकिन हमारे यहां कोई भी ग्रंथ तैयार नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि क्या आपने इस प्रकार का साहित्य तैयार कराया ?

इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से अपने संबंध अन्य देशों से स्थापित करे। ठीक है, यह देश गरीब है, आर्थिक दृष्टिकोण से हम दूसरों की ज्यादा सहायता नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राचीन काल से मध्य एशिया और अरब के देशों के और दक्षिण एशिया के देशों के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारा देश केन्द्र रहा। बगदाद जो आज हमारा विरोधी होकर खड़ा हो गया है, जब भारतीय संस्कृति का मिडिल ईस्ट सांस्कृतिक केन्द्र होता था वहां ग्रन्थों के ट्रांसलेशन होते थे और वहां से भारतीय संस्कृति ग्रीस होती हुई यूरोप में जाती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके डिपार्टमेंट में एक विभाग है इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च। नाम बहुत सुन्दर है। इतना सुन्दर नाम है कि मैंने सोचा शायद कोई सोशल साइंस पर रिसर्च की होगी। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च विभाग की ओर से कितने ग्रन्थ लिखे गये हैं, कितने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और किन किन विषयों पर रिसर्च हो रही है। विशेष रूप से मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कौन सा सामाजिक विषय है जिस पर इस इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की गई है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में हमारे सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे सामाजिक नियम और साधनों पर वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति का असर और प्रभाव पड़ रहा है, इसके सम्बन्ध में कोई ग्रन्थ आपके यहां से लिखा गया हो तो आप उस सम्बन्ध में सकेत करें।

अन्त में, चूंकि घंटी बज चुकी है, एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को 7 करोड़ का धन दिया है, यू० जी० सी० को आपने 31 करोड़ का धन दिया। दिल्ली की आबादी 40 लाख है, तमाम 55–56 करोड़ देश के लोग हैं, आपने उन के लिए केवल 24 करोड़ रखा और दिल्ली को 7 करोड़ रुपया दिया। यह दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ आपने अन्याय किया। यानी आधी परसेंट जनता को 7 करोड़ दिया है तो यह किस आधार पर दिया है ?

एक और बात मैं जानना चाहूंगा। दिल्ली में प्राइवेट कालेजेज चल रहे हैं। उन्होंने खून पसीना एक करके घर घर जाकर चंदा मागकर वे प्राइवेट कालेजेज खोले हैं।

आर्य समाज की ओर से मैं कहता हूं कि हमने न मालूम कितने इंस्टिट्यूशंस खोले और उन के लिए मालूम नहीं किस तरह से चंदा मांगा। अब जब नियत्रण का प्रश्न सामने आया पहले आपने प्रबंध समिति में ट्रस्ट के 10 रखे थे, विश्वविद्यालय के 2 रखे थे और अध्यापकों के 3 प्रतिनिधि रखे थे और अब आपने ट्रस्ट के 3 आदमी कर दिये, 2 विश्वविद्यालयों के कर दिया और 5 अध्यापकों के कर दिये। जिन आदमियों ने उन कालेजों को बनाया है और जो लोग चन्दा घर घर मांग कर के उनको चला रहे हैं उनको अब आपने अलग फेंक दिया है। जब उनका इंट्रेस्ट ही नहीं रहेगा तो इसके माने यह हैं कि

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूटावत]

इन इंस्टिट्युशंस को आप को स्वयं संभालना पड़ेगा, अन्यथा आप उनको प्रोत्साहन दीजिए और उनको अनुत्साहित मत कीजिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सहायता पहुंचा रहे हैं उनको आप उत्साहित कीजिए। इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, इसमें दो रायें नहीं है कि पिछले 25 वर्षो में हमारे देश में साक्षरता का प्रचार हुआ है। इस में भी दो रायें नही है कि पहले के मुकाबिले में बहुत बड़ी धन राशि शिक्षा के ऊपर व्यय की जा रही है। इसमें भी किसी के दो मत नही हो सकते कि शिक्षा विभाग में एक से एक शिक्षाविद् आयें जिनके हाथ इसका कार्यभार सौंपा गया। मैं यह भी मानती हूं कि शिक्षा को किस प्रकार ओरियंटलाइज किया जाय, किस पद्धति पर डाला जाय, किस प्रणाली पर चलाया जाय इसके बारे में शिक्षाविदों की एक नही अनेक मीटिंगें हुई और उन्होंने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और न जाने कितने प्लान बने, लेकिन इन सब के होते हुए भी जब हम आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से अपने मुल्क पर नजर डालते है तो हमें कई खामियां नजर आती हैं। खामियां तो हर एक काम में होती हैं और उनको सुधारा जाता है, लेकिन हमें यह नज़र आता है कि बुनियादी तौर से जहां तक शिक्षा का सवाल है हम लोग ज़बरदस्त गलतियां करते चले जा रहे है। हमारे देश की जरूरतों को देखते हुए, हमारे यहां की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बदली जानी चाहिए थी, हम उसे बदलने में बिल्कुल कामियाव नहीं हो पाये। जो ढ़ांचा अंग्रेजों ने रखा था करीब करीब उसी ढ़ांचे के ऊपर हम आज भी चले जा रहे है। इसके अलावा जो ढ़ांचा अंग्रेजों ने हमारे यहां रखा था और वह केवल क्लर्क पैदा करने का रखा था और बदनसीबी से आज भी हम केवल क्लर्क पदा करते चले जा रहे है, बल्कि मैं यह कहूंगी कि आज जो हमारा शिक्षा विभाग है वह बेकारों की गढ़ने की एक टकसाल है जहां लाखों बेकार नवयुवक गढ़े जा रहे है।

इसके अलावा जहां मुझे परेशानी होती है वह शिक्षा विभाग की एक नीति को देख कर होती है और वह यह है कि हम अपने मुल्क को जिस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस तरह की हम अपने यहां की शासनप्रणाली चलाना चाहते हैं या जिस दिशा में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा उसके विपरीत जा रही है। यदि हम मुल्क को ले जाना चाहते हैं पश्चिम की ओर तो शिक्षा ले जाती है पूर्व की ओर । देश में हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं, देश को हम सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं और मुल्क को उस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली है कैपिटलिज्म पर आधारित। हमारी सरकार समाज मे या राष्ट्र मे जो सुधार करना चाहती है उसके संबंध में हमारी शिक्षा कोई सहयोग नही देती है। इसी का आज यह नतीजा है कि हम अच्छी से अच्छी नीतियां बनाते हैं, लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नही हो पाता और इसलिए नहीं हो पाता कि कालेजों से निकल करके जो ऐडमिनिस्ट्रेटर अपने पास आते हैं वे आज की बुनियादी नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि उनको जो शिक्षा मिली है वह आज की बुनियादी नीतियों के खिलाफ है। इसलिए आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते है पूर्व की ओर, लेकिन जो उसमें बैल जुड़े हुये हैं वे

उसे ले जाते हैं पश्चिम की ओर। सब से बडी मुश्किल यह है। आप सेकुलर्जिम की बात कहते है और आप अपने मुल्क को सेकुलर बना रहे हैं। उसके ऊपर आप को नाज है, लेकिन आप जो इतिहास पढा रहे है उस मे मुस्लिम पीरियड का इतिहास है और आप की शिक्षा उस के साथ मेल नही खाती। आप का मुल्क गरीब है। आप चाहते हैं कि यहा लेबर की डिग्निटी हो, लोग लेबर की डिग्निटी को समक्ष ले, लेकिन मत्री महोदय आप जानते हैं कि हमारे कालेजो से या हाई स्कूलो से जो लडके निकलते हैं वह लेबर के नाम से ही दूर भागते है। हम रात दिन देखते हैं कि हमारे गावो के जो लडके है उन के मा–बाप किसान होते है, वे अपने हाथो से ही अपना काम करते है, लेकिन जैसे ही वह लडका स्कूल मे गया उस के बाद वह एक सेर वजन उठाने मे भी अपनी तौहीन समझता है। लेबर की कोई डिग्निटी उस के दिमाग मे नही होती। इस लिए आप जिस तरफ मुल्क को ले जाना चाह रहे है वह चल नही पा रहा है। आप जानते है कि गावो मे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार हो और गाव अपने आप मे सेल्फ सफीशियेट बने, इडिपेडेट बने और गाव मे रह कर ही लोग अपने गावो की तरक्की करे, लेकिन बदनसीबी से जैसे ही गाव का लडका शहर मे आता है उस के बाद वह गाव मे वापस जाना पसद नही करता। अगर वह जाता है तो एक नयी प्रणाली, हिप्पी प्रणाली ले कर वह गाव मे जाता है जो उस गाव मे उस को अन्यत्र कही देखने को नही मिलती। तो शिक्षा मत्री महोदय, जो हमारी सब से बडी खामी है वह यह है कि जिस तरफ हम अपने मुल्क को आगे बढाना चाहते हैं उस के लिए उस तरह की शिक्षा हम नही दे रहे हैं। अगर मैं आप को इस के सबध मे उदाहरण द् तो उस मे समय लगेगा और मैं समझती हू कि इस की जरूरत नही है, लेकिन जब हम दुनिया के दूसरे मुल्को को देखते है तो पाते हैं कि उस मुल्क के कर्णधार उस मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहते है उसी तरह की शिक्षा भी देते है। वह उन की दिशा चाहे गलत हो या सही हो, यह मैं नही कहती और मै उस मे जाना भी नही चाहती, किन्तु हिटलर जब जर्मनी मे आया तो वह अपने मुल्क को योरप मे एक फौजी ताकत बनाना चाहता था और इस लिए उस ने शिक्षा के हर पहलू मे फौजी की शिक्षा को रखा। मै यह नही कहती की वह सही था, लेकिन अरिथमेटिक मे यदि कोई सवाल भी अगर वहा होते थे तो वह इस प्रकार के होने थे कि अगर एक बम वर्षक एक घटे मे इतने बम गिराता है तो चार घटे मे कितने बम गिरायेगा। यानी बचपन से ही बच्चो को जिस दिशा मे ले जाना होता था उस दिशा मे बढाया जाता था। उस के पतन के पश्चात् जब जी० डी० आर० ने अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलने का विचार किया तो वहा की हुकुमत ने सब से पहला काम तो यह किया कि जो वहा के पुराने शिक्षक थे, जिन के दिमाग मे नाजियो का कीडा घुमा हुआ था या उन की आइडियोलोजी जो उन के दिमाग मे बैठी हुई थी, सब से पहले उन शिक्षको को वहा से हटा दिया गया। और उन को पढाने का काम किसी भी स्कूल मे नही दिया गया और उन के स्थान पर उन्होने अपनी आइडियोलोजी के शिक्षको को रखा। यह भी एक बडी दिक्कत थी कि उन के पास अपनी आइडियोलोजी के ज्यादा शिक्षक नही थे, तो उन्होने कुछ शिक्षको की सहायता

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]

से वे दूसरे शिक्षक तैयार किये और फिर उन शिक्षकों को स्कूलों में भेजा गया। लेकिन आप सोचिये कि आज आप के शिक्षक क्या करते हैं और आज यहां की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। आज आप सेकुलरइजम का बार बार दावा करते हैं, लेकिन क्या आज आप के स्कूल सांप्रदायिक चीजों का अड्डा बने हुए नहीं है? क्या आज वहां सांप्रदायिकता के बीज नही बोये जा रहे हैं? मैं कहती हूं कि आप के मिडिल स्कूलों से ले कर यूनिवर्सिटी तक आज सांप्रदायिकता के बीज ही नही बोये जा रहे हैं, बल्कि वहां शिक्षा के साथ साथ कम्यूनलिजम की शिक्षा और दीक्षा दी जा रही है। इस बात को आप को स्वीकार करना होगा। यह पहले हाई स्कूल्स तक था, अब यह बढ़ कर कालेजों और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। केवल हिन्दू यूनिवर्सिटी में ही कितनी शाखायें चल रही हैं। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कांड़ हुआ, आप के ही प्रदेश में वह क्या था? कल हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि नालंदा के बाद अपने ढंग का यह दूसरा अग्निकांड था जिस में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जलाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया गया। यह हमारी आंखे खोलने के लिए कम नही है कि यूनिवर्सिटियों में और कालेजो में इस तरह का तबका पैदा हो रहा है, पनप रहा है और फल फूल रहा है और मजा यह है कि दूसरे राज्यो मे जहां इस प्रकार की शाखायें चलती हैं वहां उन को सरकारी ऐड दी जा रही है। मैं राजस्थान की मिसाल देकर कह सकती हूं कि "विद्या निकेदन" नाम की संस्था की जगह जगह पर ब्रांचेज खुली हुई हैं उनमें खुलेआम इस तरह का प्रचार किया जाता है, इस तरह की शिक्षा दी जाती है, इस तरह की दीक्षा दी जाती है। राज्य सरकारें जानती हैं, नियम भी ऐसे हैं, कायदे भी ऐसे हैं लेकिन अफसोस है कि इन मामलों में आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कुछ कर सकते, यह हमारी बुनियादी कमज़ोरी है और कमज़ोर बुनियाद के ऊपर शिक्षा का महल नहीं बन सकता, चाहे साक्षर हो जायं लेकिन शिक्षा का जो सही मंशा है वह पूरा नही होगा और जो आदर्श और उद्देश्य ले कर आप देश को आगे ले जा रहे हैं वह सपने इस शिक्षा को बुनियाद के ऊपर पूरे नहीं हो सकेंगे।

मैं आपका ध्यान कुछ दूसरी बातों की तरफ भी दिलाना चाहूंगी। शिक्षा को ले कर के आपके यहां नेशनल बुक ट्रस्ट चलता है। मैं जानना चाहूंगी कि आज तक उसका क्या क्या कांट्रीब्युशन है। इस तरह से कई जगह है, इस तरह के अनेक ट्रस्ट या इस तरह के अनेक प्लान बना कर के सफेद हाथी शिक्षा विभाग में बांध रखे हैं जिनका कांट्रीब्युशन कुछ नहीं होता और खर्चा करोड़ों रुपयों का जाता है। मैं सिर्फ इसी का ही नहीं कहती हूं, दूसरे काम हैं, ट्रांस्लेशन का काम दे रखा है, अनेकों काम हैं, उनको देखा जाय तो करोड़ों रुपया खर्च होता है और जो हमारा मकसद है, जो मंशा है, वह पूरी नहीं हो पा रही है। हम फिर से ठीक से देख कर के कि इस महान राशि को कहां ठीक ढंग से खर्च करें जिसका कि सदुपयोग हो सके, यह देखना है। तो इस नज़र से इसको देखा जाय।

जब हम अपनी साक्षरता और लिट्रेसी की ओर ध्यान देते हैं तो अफसोस होता है। हमारा मुल्क शायद 338 मिलियन निरक्षर लोगों से भरा हुआ है। हमारे ताजे आंकड़े बताते हैं कि निरक्षरता बढ़ी है, आबादी के साथ

निरक्षरता भी बढी है। अभी उधर बोलने वालो ने कहा कि अगर दो तीन महीने ग्रीष्म अवकास मे चले जाय तो साक्षर कर सकते है। मै इस बात मे विश्वास नही करती। यह बहुत बडा काम है। करोडो लोगो को शिक्षित करना, गावो मे जा कर के करना बहुत बडा काम है, उनका जो सामाजिक बैकग्राउड है, जो आर्थिक स्थिति है उसमे जा कर के साक्षर करना बडा मुश्किल है। यह केवल अकेले सरकार के बस की बात नही है। यह तभी हो सकेगा जब कि इसमे पब्लिक को, आम जनता को, पीपुल्स को, उसमे डाले, एक ऐसा ड्राइव हो कि जो इस निरक्षरता को हटाने मे दृढ हो और तभी यह हो सकता है। केवल सरकार के बूते पर करोडो रुपया खर्च करने पर भी वह चीज नही हो सकती और न तो उसके लिए हमारी आर्थिक क्षमता है। दूसरे मुल्को मे हमने देखा है कि वहा ऐसा ड्राइव किया गया निरक्षरता को हटाने का और आम लोगो ने उसमे सहयोग दिया। अगर स्कूल की बिलडिग न भी बने तो औरते जो घर पर खाली रहती है वह वराडे मे बच्चो को बिठा दे और उनको साक्षर करे, औरतो को बिठा दे और उनको साक्षर करे। पहले बिलडिग बने, स्कूल बने, टीचर्स हो और उसके बाद जा कर यह हो तो उसमे कितना वक्त लगेगा। मै आपसे कहूगी कि आप जनता का ध्यान इसमे डाले, जनता से कुछ काम ले, जो खाली बैठे है, एक नही लाखो व्यक्ति ऐसे है जिनके पास कुछ काम नही होता, कुछ लोग ऐसे होते है जो कि भलाई का काम भी करना चाहते है तो उन लोगो को साक्षरता के काम मे लगाये। निरक्षरता को हटाने के लिए आम जनता का सहयोग होना चाहिए। (*Time bell rings*)

काफी वक्त है और बोलने वाले भी बहुत ज्यादा नही है। आप मुझे इजाजत दे।

श्री उपसभापति बोलने वाले बहुत है यही तो दिक्कत है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत तो क्षमा कीजिए, मै जल्दी जल्दी दो तीन बाते रखना चाहती हू।

हमने आर्ट प्रिजर्वेशन का पिछले समय कानून बनाया था लेकिन उस कानून के अभी तक रूल्स एड रेगुलेशस नही बने। बन भी गये हो तो मुझे पता नही लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नही हुआ। अगर हो चुका है तो आप बताइयेगा कि कितने लोगो की ऐसी जो कलाकृति– या है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इतना अधिक वक्त लगने की वजह से लोगो ने उनको अडरग्राउड कर दिया है, उनको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। इतना लम्बा समय जो लगा है उसकी वजह से यह हो रहा है। मै आपका हैदराबाद के निजाम की ओर ध्यान दिलाना चाहगी। उनके पास एक बहुत बडा आर्ट ट्रेजर है। वह खुद यूरोप मे रहते है।

चोरी-छिपे उस आर्ट ट्रेजरी की बहुत दुर्दशा हो रही है, लोग वहा की चीजे चुरा रहे है, बेच रहे है, इधर-उधर ले जा रहे है। मै नेशनल म्यूजियम की ओर भी थोडा सा आपका ध्यान दिलाना चाहती हू। आपने 3 नेशनल म्यूजियम्स किए, अच्छा किया, लेकिन म्यूजियम मे यह होता है कि अपने यहा की जो चीजे है वह तो है, बाहर की चीजे भी रखी होती है। अगर हम इस नजरिए से देखे तो हमारे नेशनल म्यूजियम मे बाहर की कला- कृतिया नही है जिससे बाहर की चीजे भी हम यहा के लोगो को पूरी दिखा सके।

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूगी वह यह कि दिल्ली मे, जहा कैपिटल है, हमारा एक नेशनल म्यूजियम है, वहा पर दर्शक लोग इतनी कम सख्या मे देखने के लिए क्यो आते है? क्या आपने इसको स्टडी किया? मैने सालारजंग का म्यूजियम हाल मे देखा। रोजाना हजारों आदमी वहां आते है। जयपुर के म्यूजियम में भी करीब हजार की औसत है देखने वालों की। लेकिन यहां पर कम क्यों है? क्या जिस तरह की चीजें साधारण लोगों के देखने की होती है उस तरह की चीजें नही है। इसके साथ मैं निवेदन करूंगी कि हमारे म्यूजियम में जो लोग ज्यादातर रखे जाते है, यह इतना बड़ा स्टाफ क्यूरेटर का लगा कर, उनको म्यूरोलोजी की जानकारी कम होती है, न्युमिस्मेटिक की जानकारी कम होती है। कम से कम राजस्थान मे न्युमिस्मेटिक जानने वाला कोई नही। उनकी ट्रेनिग का किया जाना बहुत जरूरी है। *(Time bell rings)*

बार बार घंटी वज रही है। मै एक ही मिनट मे खत्म कर दूगी। अब मैं आपका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ दिलाना चाहती हू। स्पोर्टस को लेकर ओलम्पिक्स खेलों में जो हमारी गति हुई है वह सबके दिल को तोडने वाली है। श्रीमन्, और मुल्कों ने क्या कुछ किया है स्पोर्ट्स के मामले में और क्या हमने किया है? मैने सुना है, कोई आपके हाथ मे ऐसा प्लान है कि जिसमे अलग अलग टीमों को फार्म करने के लिए, उसके लिए सेलेक्शन करने के लिए कोई पद्धति रखी गई है। चाहे पाच-चार स्पोर्ट्स ही हम चुने लेकिन अच्छे लोगो को सेलेक्ट करके उनको बराबर तालीम दी जाए, उनके लिए अलग से इन्स्टीट्यूट ट्रेनिग और कोचिग का हो और इसके साथ ही उनको छात्रवृत्ति के आधार पर जो नकद धन आप देते है वह न दें बल्कि उनको खाना और खुराक दी जाए, क्योंकि जो रुपया दिया जाता है वह दूसरे कामो मे खर्च हो जाता है। उन खिलाडियो को किस प्रकार अच्छी खुराक दी जाए, इसका आप पूरा प्रबंध करे *(Time bell rings)*

बार बार आप घंटी बजा रहे है इसलिए मै और ज्यादा नही कहूगी। आपने मुझे बोलने के लिए जो वक्त दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr Shyamlal Gupta, kindly adhere to 15 minutes strictly. Otherwise we will have to sit up to 9.00 P.M. to finish it.

SHRI SHYAMLAL GUPTA (Bihar): Well if you extend it by an hour what is wrong with it?

Mr. Deputy Chairman, Sir, we are advocating secularism. We are basing our educational system on secularism. The Education Minister will kindly bear me out. At his instance, the V.C. of the Delhi University got passed resolutions from Academic Council and Executive Council, as my friend Mr. Tyagi first referred, to make differentiation between minority institutions, majority institutions and government institutions. The V.C. has done it at the instance of the Education Minister, Prof. Nurul Hasan. Those trusts who had spent about Rs. 10 to 12 lakhs on each institution. They are now being condemned for doing this service to the country. Although this has not yet been cleared by the Ministry or by the President but the mischief has started.

Sir, the chaos in the Delhi University, as we all know, is at its height. The staff councils have opposed the opening of evening colleges and the administration of the Delhi University has given too much weightage to their opinion or to their decision. I last time also I mentioned about the surplus staff. We are pending about Rs. 1000 or each member of the staff and hundreds of teachers are surplus in the Delhi University colleges, what to talk

of other Universities My friend Mr Iyagi, mentioned about the money we spend on the Delhi University Well during the Winter Session the report of the U G C was presented and I spoke on it Seven crores of rupees were spent on the Delhi University and the Jawaharlal University out of a total of Rs 31 crores on a half per cent population of the whole country Now is it secularism Is it not famishing other areas at their cost We are over feeding a small pocket I am not against it We should pay them more but it should be equitably distributed rather than give more to one region and famish the other regions In Bihar the universities are not able even to pay the salaries of the staff and library books are not purchased by them These things have been mentioned again and again Our hon Minister is aware of all these things and let him take care of them Kerala comes next The Muslim League which is a partner in the parties forming the Government took exception to some portions in a text book and they agreed to it Now he may say that it is a State subject The ruling party is having Governments everywhere They are responsible for it They had to take out the passage at the instance of the Muslim League Is it secularism

I come to the Banaras Hindu University They are all nominated members so far What about that? Is the Vice Chancellor Dr Shrimali functioning well in the University As the reports are heard not care for any democratic set up there In regard to the Aligarh Muslim University as my hon friend just mentioned we have to appease the minorities A Bill may come here shortly just to appease the minorities and to remove certain sections to which the minorities are opposed

Now I may mention some other things The National Council for Educational Research and Training NCERT—which is a wing of the Ministry of Education is responsible for the preparation of text books manuscript and the sale of books Our students are without books for six months because the officers working there are most inefficient They are not able to provide *text books to our students* I can prove it by whatever evidence the Minister may want me to produce During the winter session I had asked the Minister of Education about the working of the Hindi Directorate We must have spent about Rs 10 crores on its working during the past twenty years Now what is the result The Minister had very kindly agreed to give me the details but as is the case with all the Ministers, these are never looked into I had specifically mentioned about the money you had advanced to publishers for translations of books which have never seen the light of day and they will never see the light of day All the money has been wasted Why all these things The administrators just throw away money into the gutters We say that the money allocated is less than what we want Well if the money which we budget for is well spent then it can bring in a better result, than asking us for more and more grants The Education Minister may or may not agree with me But I am of the opinion that we do not spend the money in a rightful manner so that more and more education could be spread by the money which we get We do not want more money The Ministry of Education should work well the administrative charges should be much less than what they are today Well I will not take much time about that

During the winter session in reply to my question the Minister had very kindly consented to go into the details of the publications of regional books translation of books into the regional languages Nothing has been done so far I have sent two or three letters to the Education Minister and to the Chairman of the University Grants Commission But no reply has so far been received because these are questions which are unpalatable and why should the Education Minister or the Ministry's officers take cognizance of it Well we have spent crores of rupees and we are wasting it Let the money be spent and be wasted This attitude is very much against the welfare of the State

Most of the States have nationalised books Books are the media for the spread of education I would request the Education Minister Prof Nurul Hasan to collect those books and see the quality whether we are able to provide books of a high quality to the students of those States They are always far behind the schedule when the colleges and the schools open If a private publisher is not able to publish a book in time there is a penalty

[Shri Shyamlal Gupta]

clause, but there is no such penalty clause in regard to others. They are superhuman, they are above all others and the officers are answerable to none. Now, Sir, take the National Library, Calcutta. Everything is in the doldrums. There is the Rajah Ram Mohan Roy Trust. About a crore has been earmarked and what is the outcome? The National Book Trust's publications are being dumped into the library. And after the money has been spent we shall have a report that so much money has been spent on Rajah Ram Mohan Roy Trust Library although not much will come out of it. The National Book Production Board was started about 10 years ago. What is the outcome? What work have they done? What has the Government done to improve the productivity of books and what have they helped about the indigenous production of books which are the media of the education of children? As mentioned by our sister here what about the athletes, or students welfare? You are responsible for youth welfare also. Is it their welfare that in all the campuses the students are going out of the hands of the teachers and even the Vice Chancellor is not able to control them? It is only because our policies are wrong. In Delhi the staff of a college have 18 periods to teach out of which 8 to 10 are preceptorials. Nobody is interested. The students or the teachers, they do not care. Why? Because the University condones absence from them. The idea was very laudable. The idea was to have small groups of students to give them good teaching to sort out their difficulties. But actually it is not being done. Why? Because among the teachers nobody wants to work. Will the Education Minister kindly look into it? If need be I can explain to him personally. He is a busy man and will not have time. I addressed him two letters about it but no reply so far has come. I do not think even my mention here will bear any fruit. But I think it is my duty to mention whatever I feel about it.

Sir, the surplus staff of the colleges, as I said last time also, creates mischief mongering. On the Delhi colleges we spend Rs. 7 crores but what is being done with this money? The surplus staff is there but there are no boys to teach. What is the fun in wasting so much money of the nation if the staff does not work? I have been mentioning this for the last two years to the Vice Chancellor and even to the Chairman of the U.G.C. and the Minister himself but nothing has been done because we are afraid of the Union of the teachers. They have to be appeased, otherwise the chair of the Minister and the Vice Chancellor will shake. If we have to administer these things should not deter us from the right path.

Other have taken up so many other points. I will not repeat them. But I will request the Education Minister who is an enlightened person and a teacher himself to try to take action on the points which we have mentioned here and if he thinks fit he may take us into confidence and we will certainly help him in many matters.

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) उप-सभापति महोदय, मै आपके विवाद मे सबसे पहले जो शिक्षा मत्रालय मे मत्री है उनके द्वारा जो एक विशेष कार्य हुआ है, उसकी तरफ लोगो का ध्यान दिलाना चाहता हू कि जहा तहा प्रदेशो मे ग्रथ अकादमिया बनी है और उन पर द्रव्य खर्च किया गया है इसलिए कि भारतीय भाषाओ मे वे ग्रन्थ उपलब्ध हो सके जो विदेशी भाषाओ मे है और हमारे यहा नही है, जो तकनीकी ग्रन्थ है जिनकी बहुत आवश्यकता है, तो जो काम विभिन्न सूबो मे हुआ है, जो प्रतिवेदन आपा है इन ग्रन्थ अकादमियो का वह बडा सतोषजनक है।

दूसरी बात मै यह कहना चाहूगा कि जो योजना यहा से प्रसारित की गई थी कि जो किशोर और तरुण विद्यार्थी है उनको काम मे लगाया जाए, छुट्टियो के वक्त उनसे काम लिया जाए, श्रम भी और पढाने का भी, जिन्होने भी इस बात को पकडा है और जहा जहा यह काम हुआ है वहा उल्लेखनीय प्रगति दिखाई पडी है और एक प्रकार से उपद्रवो से विद्यार्थी बचे रहे है। जो यहा से प्रारभिक शिक्षा के सम्बन्ध मे, माध्यमिक

शिक्षा के बारे मे और उच्च शिक्षा के बारे मे अच्छी से अच्छी योजनाये चली और पाचवी योजना मे क्या उपस्थित किया जाए वह भी अच्छी से अच्छी चीजे सामने आई। सहानुभूति से विचार करने का, सोचने की बात यह है कि केवल इस वक्त ही नही, इन 25 वर्षो मे शिक्षा मत्रियो और शिक्षा मत्रालय ने अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन किया, समस्याओ पर अच्छे मे अच्छे प्रतिवेदन उपस्थित किये है और फिर भी जो परिणाम प्रस्तुत है देश के सामने वह करीब करीब शून्य है।

ये छोटी छोटी बाते जो अभी कही उनको छोड कर । जो मुख्य कठिनाई शिक्षा मत्रालय और शिक्षा मत्री की ह वह मै इस तरह से सोचता हू कि सब से बडी विषमता जो सविधान ने शिक्षा की स्थिति की कर के रखी है वह इसका मुख्य कारण है और इसी मुख्य कारण मे से अनेक विषमताओ ने फैल कर के शिक्षा के क्षेत्र को जो नही बनना था वह भी बना दिया। उदाहरण के लिए अच्छी से अच्छी योजना यहा से जाय और कोई प्रदेश उसे न लागू करे तो यहा से क्या किया जा सकता है। इसी तरह से अच्छी से अच्छी योजना प्राथमिक शिक्षा की भेजी जाय और जिन के हाथ मे प्राथमिक शिक्षा चलाने का अधिकार है, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे वह कारपोरेशन हो, वह उसे लागू न करे, उस दिशा मे न जाकर और दिशाओ मे जाय तो क्या किया जा सकता है। इसी तरह से युनिवर्सिटियो मे, उच्च शिक्षा मे भी यहा से कोई नियत्रण नही है। यू० जी० सी० इतना पैसा देता है और जिन को पैसा देता है वे स्वायत्त सस्थाए है और उन स्वायत्त सस्थाओ मे जो विद्यार्थी है वे बड़ी उम्र के हो जाते है कालेजो मे पहुच कर के और वे उच्छृखल हो गये है ठीक मार्गदर्शन के अभाव मे या यह समझिये कि इन विषमताओ के प्रभाव से।

एक और यह मुख्य विषमता है कि शिक्षा की प्राथमिक शालाए भी अनेक प्रकार की है जिन मे अनेक शासन उनके उत्तरदायी है। ठीक इसी प्रकार सरकारी माध्यमिक शालाए है, पब्लिक स्कूल्स है और और तरह के स्कूल्स है। इसी तरह से उच्च शिक्षा मे भी प्राईवेट कालेजेज है और गवर्नमेट कालेजेज है और युनिवर्सिटी की अपनी शिक्षा अलग चलती है। कही पर युनिवर्सिटी कालेजेज को अफिलिएट कर के चलती ह और युनिवर्सिटी का अपना शासन कालेजेज पर नही चलता है।

जो शिक्षक और शिष्यो के सम्बन्ध पुराने जमाने से चले आये थे वे सब टूट-फूट गये है। सब जगह द्रव्य चलता है, पैसा चलता है, पैसे से सब चीजो को खरीदा जा सकता है। फर्स्ट क्लास भी इम्तहान मे, परीक्षा मे, खरीदा जा सकता है और ऐसा होता ह । आतककारी प्रवृत्तिया शिक्षा के जीवन को प्रभावित कर रही है जो सर्वत्र दिखाई देती ह। अभी कल ही उदाहरण यहा पर आया और जो कानून और व्यवस्था का प्रश्न था उसमे भी विद्यार्थियो का उल्लेख हुआ । पुलिस मे विद्यार्थियो की साठगाठ का एक नक्शा उपस्थित हुआ जिसमे लखनऊ मे अराजकता की स्थिति पैदा की और एक भयकर अग्निकाड हुआ शिक्षा के क्षेत्र मे। इन विषमताओ की जड को खोद कर जब तक नही बहाया जायगा तब तक जो भी वचन हम देते है, जो भी उद्देश्य हम सामने रखते है सब इसी प्रकार मे असफल होते चले जायगे। कौन ऐसा ईमानदार शिक्षाविद् नही है जिस ने ऐसा महसूस न किया हो, यह स्वीकार न किया हो कि

[पडित भवानी प्रसाद तिवारी]

शिक्षा की पद्धति को आमूल बदलने की आवश्यकता है, मगर जैसा कि सकेत किया गया कि कही कोई आमूल परिवर्तन हो नही सका। अच्छे से अच्छा रिसर्च वर्क हमने जरूर इकट्ठा कर लिया, पर हम किसी के जीवन मे कोई परिवर्तन नही कर सके। जो अभी त्यागी जी ने कहा उनकी बात को मै दूसरी तरह से कहता हू कि गाधी जी ने इस सबध मे यह कहा था कि यदि शिक्षा मे चरित्र निर्माण का कोई काम नही हो रहा है तो मै उसको कोई महत्व नही देता।

आज तो यह दिखायी देता है कि शिक्षा के क्षेत्र मे चरित्र निर्माण की कोई गतिविधि नही है, बल्कि लोग उल्टी ओर चल रहे है और इस वजह से यह आवश्यक हो गया है कि सोचा जाय कि क्या कोई एक शासन इस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी समझ लीजिए कि केन्द्र का शासन होता है, वह ही सारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को अपने हाथ मे ले कर चले और वह पार्लियामेट के प्रति उत्तरदायी हो ताकि हम यहा सरकार से पूछ सके कि क्या कारण है कि आप के प्रयत्न करने के बाद भी कोई नतीजा नही निकल रहा है, अच्छी से अच्छी योजना के नतीजे भी सामने क्यो नही आ रहे है, तो वह बता सके कि इस का कारण यह है। इस समय तो हम केवल एक ही उत्तर सुनते है कि यह तो हमारे क्षेत्र मे नही है, यह तो स्टेट का विषय है, उस के क्षेत्र मे है तो उस मे हम क्या करे। यही स्थिति हमेशा पैदा होती है। इस स्थिति को बिना मिटाये, जो यह सवैधानिक विषमता इस की जड मे है इस को बिना तोड न तो आप पद्धति बदल सकते है और न आप जो आदर्श बनाते है, जो आदर्श उपस्थित करना चाहते है वह कर सकते है और ऐसा रहने पर आप चाहे अच्छे से अच्छा मार्ग दर्शन भी क्यो न दे परिणाम हमेशा घटता हुआ ही मिलेगा, शून्य ही मिलेगा और यह दुर्भाग्य की बात है। आप ने देश मे सब कुछ बनाया। आप ने उद्योगो का निर्माण किया, खेती के औजारो का निर्माण किया, जो नयी दुनिया से आप का सपर्क हुआ उस से तरह तरह के निर्माण आप ने इस देश मे किये, परन्तु पीढी निर्माण आप नही कर पाये और उस के कारण शिक्षा के क्षेत्र मे जो मूल विषमता पैदा हुई है और जिस का बटा हुआ क्षेत्र है, जिस के लिए कोई उत्तरदायी नही है, इस स्थिति को बिना मिटाये आप कुछ नही कर सकते और ऐसा न होने पर यह अराजकता बढती ही जायगी और इस की कही रोक नही होगी। आप देखिये न, पहले विद्यार्थियो को नियत्रित करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पडती थी, अब पुलिस और विद्यार्थियो की युनि को रोकने के लिए मिलिटरी की आवश्यकता पडती है। यह क्या शिक्षा का क्षेत्र है? यह हम क्या कर रहे है? आप इन विषमताओ पर प्रहार करिये। शिक्षक आज बिक रहा है और जब वह बिक रहा है तो यह विद्यार्थियो को क्या सिखायेगा, क्या उन का चरित्र निर्माण करेगा। तो श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि अपने आदर्श और अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए इस विषमता पर आघात करना आवश्यक है।

जहा तक सस्कृति के मूल का प्रश्न है, मै त्यागी जी से इस मामले मे सहमत नही होता । वह हमेशा ही किसी न किसी बात मे नाच गाने की बात छेड देते है।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : यह भी अच्छी बात है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सुनिये, मे ने आप को सुना है। मै आप से कहता हू कि आप ने कही सस्कृति की बात। कहा संस्कृति की परिभाषा कीजिए। परिभाषा तो इतनी सहज है कि युगों युगो से जो आप के आचार, विचार, सभ्यता साहित्य और कला चली आ रही है यह सब कुछ आप की सस्कृति है और उस की अभिव्यक्ति विभिन्न विधाओ मे होती है और जो विभिन्न विधाओ में उस की अभिव्यक्ति होती है उस मे एक विधा आप का साहित्य भी है जिस मे तुलसीदास आते है, सूरदास आते है, कबीरदास आते है और रवीन्द्र आते है जिन्होने सदेश दिया सारी दुनिया को। एक विधा उस की सगीत भी है जिस मे अभी अभी आपने विष्णु पलुस्कर का नाम लिया, रविशकर जो दुनिया भर में सितार लिये फिरते है वह क्या भारतीय सस्कृति का सदेश नही देते? (**व्यवधान**) मैने तो अकादमी की बात नही की। मै तो कह रहा हू कि यह सस्कृति का सदेश ले कर जाते है। आप अगर बीच मे बोले तो आप को होशियारी से बोलना चाहिए। मै यह कह रहा था कि ठीक इसी तरीके से जो आप के नृत्य करने वाले है, जो कर्नाटक नृत्य और दूसरी तरह के नृत्यो के विशारद है वह अपने घुघरुओ की झंकार के चलते ही भारतीय सस्कृति का सदेश देते है।

श्री ओउम प्रकाश त्यागी श्रीमन्, एक प्वाइट आफ आर्डर है। मै जरा माफ कर द। मैने यह कभी नही कहा कि नाच गाना सस्कृति का अग नही है। नाच गाना भी संस्कृति का अग है लेकिन यह संस्कृति का अग है मूल आधार नही है। यह ललित कला है।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी यह सब कहा है, अच्छा, सुधार कर कहा है। मूल आधार मै कोई नही मानता। मै तो तीन विधायें बता रहा हू ललित कला की और यह भी कहना चाहता हूं कि सास्कृतिक स्थितियों पर लोग जागरूक है, देश मे जो तीन अकादमियां हमारे यहा चलती है उनके काम के सम्बन्ध मे, उनके सम्बन्ध मे, शिकायतें भेजी है, उसके ऊपर मंत्रालय की तरफ से कमेटी बनी खोसला कमेटी बनी, उन्होने रिपोर्ट दी, शिकायते दूर करने के उसमे जो कुछ नये नये विधान है उन पर विचार हो रहा है तो मै जानना चाहूगा कि यह बात कहा तक आई और अकेडमी जो इन पर विचार कर रही थी तो वह कौन कौन से सुधार है जो अकेडमी स्वीकार करेगी और उनसे क्या परिवर्तन इन अकेडेमियों में आयेगा।

तो इस तरह से यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक संदेश यहा से जावे, हमेशा जावे क्योंकि इतनी पुरातन सस्कृति और है नहीं जितनी हमारी संस्कृति है और इसीलिये मै इसी बात को दुहरा कर खत्म करता हू। आप ड़ को पकड कर के उसको हटाइये, विषमता को दूर कीजिए, इस मुख्य विषमता को दूर कीजिए और जो विभिन्न विषमता फैली है वह आप से आप इसी से दूर होगी और एक नियत्रित शासन हो जो कि जवाबदार हो देश के प्रति। क्यो शिक्षा का अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन हमारे पास हो कर के भी हम परिणाम कुछ पैदा नही कर सकते और एक अराजकता फैली हुई है।

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal) Mr. Deputy Chairman, today when fissiparous tendencies are really invading the deeper channels of national life, integration is the all out need on all fronts,

[Shri Sasankasekhar Sanyal.]

particularly in education. But I am sorry to say the real absence of purposefulness is the keynote of the present educational policies of the Government. We are talking on the poor peasants, agriculturists and the underdogs. But university education is denied to 80 per cent of these people. Eighty per cent of the people get only tinkering grants for primary education and twenty per cent of the people get the cream of the Government revenue for college and university education. The result is that even talented boys among the peasantry, after passing the primary education, in the absence of any opportunities for higher education either through proper scholarship or stipends or otherwise, they go back to the plough and they forget the little education that they got in the primary class. And it is only the upper class people, the 20 per cent of the people, who get the advantage of higher education through colleges and universities, have all the State advantages, advantages of Government service, advantages of education and all that. All these advantages are made available only to this class of people and they are literally denied to the underdogs. This is not only a policy against modernism, but also the Congress, I hope, has not forgotten Mahatma Gandhi yet . . .

SHRI M. RUTHNASWAMY: They had forgotten him long ago

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: I am glad you have said it. Even if Mahatma Gandhi is to be remembered now and then, once in a blue moon, his basis of the basic education scheme was that the people, the majority of the people, should be given such education which will make them appropriately applicable and adaptable and available for the public purpose in accordance with the respective talents of these people. May I ask my friend Prof. Hasan who is not only an educationist, but has chosen education as a career, whether he has forgotten all about the underdog.

Regarding these Public Schools, I will give you one example. In Dehra Dun there is a Public School. There is a rat race among the big people to get their children admitted there. Each student has to spend about Rs. 700 a month. Who are the parents who can spend like that? No doubt they are black-marketeers. And this education is taken as stepping stone for further education, abroad. And they come back to the country and sit on our shoulders. That means, blackmarketeers rule the country. I am sorry to say that many of our Ministers, if not all, are also sending their children to such schools. They do not send their children to institutions and schools where 85 or 90 per cent of the children take education. But they send their children to such schools which are practically un-national and anti-national.

I will now give you a startling disclosure. The Frank Anthony School in New Delhi is a Public School. Do you know that Oxford University has published a book called "Certified Regional Geography Monsoon Asia". This book is taught in that school. And this is only one link in the chain of Frank Anthony Schools all over the country. Frank Anthony is not a stranger to us. If you walk across the Central Hall to the other side, you will find him. Now I will read a portion from this book:

> "This Himalayan State of 82,000 square miles with its strategic location, its beautiful scenery and the source of the Indus is in a difficult position

This is about Kashmir. Then it goes on to say:

> "80 per cent of its 5 million inhabitants are Muslims and wish to join Pakistan."

Shall I read it again for Prof. Hasan?

> "This Himalayan State of 82,000 square miles with its strategic location, its beautiful scenery and the source of the Indus is in a difficult position. Its Maharaja is a Hindu and joined Kashmir to India, but 80 per cent of its 5 million inhabitants are Muslims and wish to join Pakistan."

It further says . . .

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): May I request the hon. Member to let me have the name of that book?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: This is a publication by Oxford University Press. The name of the book is "Certi-

fied Regional Geography—Monsoon Asia". I can lend you this book, or I will sell it to you, if you like. Since my friend wanted me to give him the name of the book, may I ask him in passing whether this is the first time that his attention has been drawn to this book? If that is so, you ask your Directors and Inspectors of your costly Department whether this is the first time that they have seen this book If they have not seen it before, sack them. Or, if they have seen it and still passed it for consumption by the children, accuse them of high treason. Is my friend prepared to do it? What is he going to do? This book is being taught in a public school and some good money is spent for that. This appeared in a paper called "Century" dated July 7, 1973. My attention was drawn to this Century caption and then I looked at the book I rubbed my eyes and strained my eyes. But I saw the same thing written in it. This is atrocious. Arising out of this, may I ask my friend whether he is going to confiscate this book.

SHRI PITAMBER DAS: Ours is an open society.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Confiscation is also an open punishment.

SHRI G. A. APPAN: He will not do so.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Let him say so.

SHRI G. A. APPAN: He will not have the courage to do that.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Prof. Hasan, you kindly go deeply into the matter and consult the school authority. You must enquire how such books are given to the students.

Secondly, you must ask the Directorate and the Inspectorate concerned how it escaped their attention or how it was not brought to your notice.

SHRI G. A. APPAN: Sir, I am on a point of order. Will the hon. Minister promise on the floor of the House that he will take action immediately and report the facts to the House tomorrow?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Appan, this is no point of order; it is a point of disorder.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Therefore, Prof. Hasan, I want to know whether you are going to inquire into this or not. I also want to know whether you are going to ask the school authorities and your Department to explain and whether you are going to take any action if they cannot give satisfactory explanation. I will now ask for the last thing. If he fails to make amends for it, as a gentleman it is his duty to resign from this office.

I will tell you another thing also about this book and you will know what misleading information is given here. I will read out from page 3:—

> "The capital of the country, New Delhi, is situated on the banks of the Jamuna, a tributary of the Ganges. Like the other Indian rivers, the Ganga has also great religious significance. It is regarded as a sacred river by the Hindus because Lord Buddha, the founder of Buddhism, is believed to have been born there."

This is what this book says about the river Ganga. Dr. Chatterji, the educationist, will probably ask: Is this the kind of education that is imparted through our public schools? Buddha was not born on the banks of the Ganga. He was born in Kapilavastu and there is nothing like the Ganga there. So, what I am saying is that this state of anarchy is there in the field of education and if you cannot prevent this sort of anarchy, then there is no use coming here with projects of education and asking for crores and crores of rupees. It should not be so particularly when we are sending so many people for higher education. After all, there is no use in having a golden image with feet of clay. Your image is glittering and all that glitters is not gold. But, all the same, the feet of clay are there. I am not saying this in a spirit of acrimony and it is not in a spirit of pride also that I am saying this. I am not a very scholarly person or highly educated person. I am only a little-read man and I read now and then. Unfortunately, the other day when I read this book, it came as a bolt from the blue.

I can give you another instance to show how anarchy prevails in education. Sir, a gentleman, by name Shri D. H. Sharma—forget the name—was the Principal of the Government Higher Secondary School in

[Shri Sasankasekhar Sanyal.]

Subzi Mandi in 1971. He got a State award for being a teacher of outstanding qualities. This is only an illustration. Now, according to the Government conventions and rules, the recipients of such awards get a medal and automatically they get two years' extension. So, after the extension, he ought to have retired in 1974. But, Sir, he was suddenly terminated on 30-10-1972 without assigning any reason. I am telling you this to show that such things are happening. After all, is it the whim of somebody in the department who lose these things? Is there any invisible ghost what haunts the directorate and directs its policy?

Therefore, Sir, I submit and maintain that the class character of education is there very much. It was not only there before, but also it is increasing now and it is because our representatives, the Ministers, are constantly in the pockets of these classes, these monopolists and the bureaucrats. These people are no longer directing our bureaucrats, but the bureaucrats are directing both the Ministers and those in the educational field. We are in the same darkness. We asked: Let there be light. But there was no light. There was eternal darkness and there is eternal darkness and it continues to be eternal darkness only. Thank you.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) in the Chair]

SHRIMATI RATHNABAI SREENIVASA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, today the education system in our country presents a dismal picture. After 25 years of Independence we are still carrying on the burden of the system imposed on us by the Britishers. While the system needed a thorough overhauling to suit the needs of our country, we have tried to do some patch work here and there by making some changes in the curriculum or syllabus on a number of years of schooling, etc., which have had only adverse effects Our children have become victims of our half baked experiments. The whole system of education at all levels needs radical reforms.

The Government had given us an assurance that within ten years of the promulgation of the Constitution, education will be made free and compulsory up to the age of 14 years. But today there are more than 386 million illiterates in our country as compared with 298 million in 1951. We have more than half of the world's illiterates. With the majority of the masses illiterate, we cannot make any headway towards progress Subjects of Food and Education should receive top priority in our planning. But the Budget allotment under Education is very inadequate In the Fourth Plan the allocation is only Rs. 824 crores which is 5.2% of the total outlay and in the Fifth Plan, though it is Rs. 2200 crores, it is only 6.4% of the total outlay. To tackle the stupendous problem of illiteracy, at least 10% of the total outlay should have been allotted to Education. However, I am glad that in the Fifth Plan, primary education rightly gets a priority by getting Rs. 1,100 crores, i.e. 50% of the total allocation on Education and a considerable outlay has been proposed on vocationalisation of studies at the High School level.

Sir, I know that a great deal of progress has been achieved in the provision of educational facilities and the bulk of the masses hitherto deprived of educational opportunities have had increased access to education. But this expansion has not kept pace with our needs of the time. The rapid expansion has created many new problems and has failed to achieve the benefits expected. The more outstanding of the problems are, one, a deplorable decline in the quality of education and, two, creation of rising expectation in the young, without providing them with the resources or opportunities to fulfil them. Young educated men and women are choosy about their jobs. Even the rural educated youth want jobs in cities only. This has created not only the problem of large-scale unemployment among the educated, but it is also responsible to a great extent for the highly explosive situation prevailing now in the educational institutions. Indiscipline, communalism and politics have seeped into the field of education also. Copying in examinations—that too mass copying—has become a normal feature of the day and students feel it is their right and privilege to copy. Not a day passes when we do not hear of agitation, violence and anarchy in educational institutions somewhere in the country. This means that no importance is

attached to the content of education but only to the degree Character building and a national outlook should be the main objective of education and our educational system, including the system of examination, needs radical reforms

I admit that the Government is making efforts to raise the standards of education at all levels The proposal to establish model community schools at the block levels and District level, intended to be pace setters with modern curriculum and adequate hostel facilities, is welcome as an attempt to raise the standards of education It is heartening to note that 25% of the seats will be reserved for children coming from the socially and economically backward groups and that they will be given full maintenance grants.

While the Central Schools, or Kendriya Vidyalayas, are maintaining a high standard of education, we should also be careful that we are not laying the foundation for another class conscious group in our society These schools must be open to all children who possess merit and qualifications and some seats for deserving children of the poorer classes should be reserved and these should get full maintenance grants.

I welcome the educational technology project for providing integral instruction by making use of films, radio broadcasts and new educational techniques

Just as the Government has established Central Schools in all parts of the country, Central Universities should also be established in all parts of the country to bring together the youth from all parts of the country and to enable them to live in harmony and friendliness, thereby promoting national integration These Central Universities should be free from a communal character whether of a majority community or of a minority community While on this subject, I would request the hon Minister to consider the possibility of establishing a Central University in Andhra Pradesh

While I do not hold that higher education should not be open to all, I feel that admission should be regulated and only those who have an aptitude for higher studies should be admitted We have to keep in mind the stupendous problem of unemployment and be aware of the fact that we cannot go on producing graduates, engineers or doctors, without taking into consideration the employment opportunities High priority should be given for vocationalisation at the Higher Secondary stage so that many people will be in a position to go in for a vocation after finishing the Higher Secondary School. If such people wish to continue their studies, opportunities should be provided for them by opening evening classes in colleges wherever necessary

One of our major problems is that of the out of school youth between the ages of 14 and 25 years Both Government and voluntary welfare institutions should make all efforts to provide these young people opportunities for physical culture, recreation as well as continuing their studies if they so wish Their cooperation should be sought in all our programmes of nation building so that they develop a modern outlook and a sense of identity with our national aspirations I hope that the Yuvak Kendras proposed to be established in the Fifth Plan and the youth movement will go a long way to achieve this object and to bring the non student and student youths together and help them understand each other and help each other

I have a word to say about the status of teachers, especially at the elementary level We are told that by the end of the Fourth Plan, an additional total number of 90 000 teachers are expected to be provided for as one of the measures to tackle the problem of educated unemployment But we should take care that we draw only the best talents to this most important profession Only those who have passed meritoriously in their qualifying examination and only those who have an aptitude for teaching should be selected as teachers and their remuneration should be adequate to attract really good teachers

Finally, I think that education should be a concurrent subject The States while they may be expected to cope with general education, have no resources to cope with the problem of High or Technical and

[Shrimati Rathnabai Sreenivasa Rao.]

Professional Education. If education becomes a concurrent subject, the Centre will have a scope for laying down certain uniform practices and establishing certain healthy standards.

DR. / A. AHMAD (Uttar Pradesh): I do not want to make general observations about education. I think, on Friday we have a Private Member's Motion and we shall get opportunity to express our views on the problems of education in a general way.

I want to concentrate today on the question of Aligarh University and the implementation or enforcement of the Aligarh University Act. You will remember, I was one of those persons who supported that Act. I stated that it was essential that in all educational institutions, communal trends or communalism, whether by the majority community or the minority community, should be curbed and we should give more and more emphasis or orientation to education in the secular direction.

4 P.M.

Obviously, the main idea in my mind was that both in the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University there have been, in the past, communal trends or communal forces of a reactionary character which have been trying to give a peculiar communal orientation to the educational system there and trying to dominate those institutions. Really we wanted an Act or a Constitution Order for those universities which would effectively curb communal tendencies. At the same time, I remember I requested the hon. Education Minister that it would be better to refer the Bill to a Select Committee because, as you know, Aligarh is a very sensitive spot and whatever laws you make about Aligarh, there was bound to be a lot of noise about them and it would be better to give an opportunity to the various points of view to be expressed in the Select Committee and ultimately come to a consensus. But at that time the hon. Education Minister was in a little hurry. I can understand that because we were pressurising him to bring an Act quickly. Seven years had passed and there was no constitution for the university. The university was governed from here and, therefore, we felt that it would be better to go through the enactment quickly. Looking back, I think it would have been wiser to refer the whole thing to a Select Committee. I say this because the Aligarh Muslim University Act has created a situation in which we find that we are not yet in a position to implement that Act. I have been appointed a Member of the Court but I have not yet had an opportunity of attending a meeting of the Court; it has not been possible to call a meeting of the Court for certain technical reasons.

And the reaction that the Act has created, the impact that it has created on the minds of the people who are emotionally and culturally attached to the Aligarh Muslim University has been tremendous: It has been an outburst. I would assess that outburst in my own way—subject to correction—but it has created a powerful impact for good or bad—and widespread opposition to that Act has come into existence.

The Aligarh Muslim University has been traditionally a university with which the Muslim community has been deeply connected—connected emotionally and culturally—because it was the centre—as I stated in my earlier speech—of Indo Muslim culture. It was, I would say, for a number of years the centre of Indo-Muslim culture. Scholars and students from all parts of India—not only from the North but from the South also—even from Kerala, the extreme South—came to the Aligarh Muslim University. Not only the educated classes but the mass of the Muslim population considered it to be a valuable seat of learning which preserved and safeguarded their cultural heritage and their place in the composite culture of India. Now, I think, we should have been a little careful about it. What is happening now? An impression has been created throughout the country that this Act serves to wipe out the traditional and cultural character of this university, that it has sought to annihilate that centre, to eliminate that centre and to create, in due course of time, a university which will be like any other university where not only in respect of internal management of the university or the governance of the university but in all other matters it would have no specific character of its own, no historic character of its own. And, therefore, the Muslims

at large have begun to feel the overwhelming majority of Muslims feel that they will lose something which is precious to them Now I would not like this impression to be created I think in a democratic, secular State like India we have to preserve certain cultural values We have to be careful about the cultural values particularly of minorities and in a democracy, in a secular State due attention has to be paid to the problems of the minorities their sensitiveness their susceptibilities and their legitimate demands If an impression goes round that Aligarh University is to be annihilated, I think it would be wrong It would harm us It would harm our democratic life It would antagonise the vast mass of Muslims who today should normally come into the mainstream of our national life who should be integrated with the progressive forces in the country and who should be detached from their earlier communal background They should feel that they are in this big country marching forward shoulder to shoulder with the other communities, that their cultural life and their cultural values are preserved, that they have a sense of their own, that they are allowed to develop their culture and preserve their culture

श्री ओउमप्रकाश त्यागी : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अहमद साहब ।

DR Z A AHMAD I do not want your remarks I heard everything patiently You should listen to me with patience I do not agree with those who in the name of secularism want to protect Hindu communalism I do not want to encourage those who in the name of secularism want to protect Muslim communalism I want real protection for the minorities so that the minorities may get integrated with the growing common life of the majority and minorities That way we have to develop a common outlook and a common life Now, if I am allowed a little more time and I would request you to give me a little more time I would say that this Act needs to be amended and it should be amended It may be asked Will it not be a climb down? Shall we not be placating Muslim communalism? Would we be climbing down before Muslim communalism if we amend this Act? No After all we are in a democratic State We pass laws We also see what impact those laws have on the minds of the people and how the people react If there is an adverse reaction and if that is being utilised by reactionary elements against the growing progressive life of the country, then surely we have to pay attention to the situation in order to win over the better elements and isolate the reactionary and communal minded Muslims from the vast mass of people We can carry out certain amendments and assure the vast mass of the Muslim population that their centre of learning, that their centre of culture is not being annihilated It will be preserved and it should be duly protected Then there is nothing wrong in amending this Act I tell you it would be useful if in this House itself the hon Minister later on puts forward some amendments which could be discussed and which could be passed There is nothing wrong in it We go on amending so many laws Now in what directions I would like the Act to be amended? There are two aspects One aspect is that of internal administration I do think that the Act as it is makes the Vice Chancellor much too powerful The whole scheme looks nice on the face of it I have gone through the note circulated by the Education Ministry where comparisons have been made in regard to the Aligarh University, the Banaras Hindu University, the Delhi University and all that Superficially it would seem that this Act is quite good and a little more progressive from the point of view of internal administration But in totality the checks and balances in this Act have been evolved in such a manner that ultimately it is the Vice Chancellor and the Executive Council or I would say the Vice-Chancellor in Executive Council who becomes the supreme authority I do not want to make any odious comparison There used to be the Viceroy in Executive Council I do not want to say that, but here the Vice Chancelor in Executive Council becomes the supreme authority

And since it is a Central University under the direct control of the Centre, ultimately it is the Central Government that overshadows it through the Vice Chancellor Analysed from that point of view, I think we have gone a bit too far The democratic functioning and the internal autonomy of the university are quite precious Shri Nurul Hasan is a professor of

[Dr Z A Ahmad]

outstanding merit and he would agree with anyone who says that the internal autonomy and the democratic functioning of the university should be preserved and fostered

Now, you see the composition of the governing bodies Start with the Court The Court has been divested of its supreme authority It was the supreme governing body It ceases to be the supreme authority, it just discusses in a general way the functioning of the University, passes resolutions on the budget and all those sorts of things It is no longer supreme

Then the Executive Council has been constituted in a manner that most of its members will be directly or indirectly nominated by the Vice Chancellor The heads of departments do not rotate on the basis of seniority but on the recommendation of the Vice Chancellor are appointed by the Executive Council Then again if there is a Vice Chancellor with bad intentions he can so function freely through the Executive Council, which now becomes the chief executive authority He can constitute the Executive Council in such a manner that it will be entirely at his mercy All powerful he becomes, and the Vice Chancellor functions directly under the Central Government

Therefore, I say that the checks and balances provided in the Act have to be looked into and examined to find out whether we can bring about any change in the distribution of the powers as between these various governing bodies The existing checks and balances should be so changed as to give an assurance that it will not be one big boss sitting there with an Executive Council who will rule over the whole university under the dictates of the Centre, with the internal democracy of the university and, in a large measure, the autonomy of the university not being there I think that this situation should be looked into and examined I am an old boy of Aligarh, and I feel very sorry that we have brought on the statute book into it something which has roused the indignation and opposition from all quarters The university teachers are not satisfied for various reasons, the university students are not satisfied the teaching staff is not satisfied and the non teaching staff are not satisfied And most of the Muslims who send their boys to the university they are not satisfied

SHRI B T KEMPARAJ Public are not satisfied

DR Z A AHMAD This situation needs examination We have created Students Councils But have we not deliberately bypassed the Students Union? Normally in all the Universities it is the Students' Unions who traditionally, historically, become the organs of the students Now a new body will be created and it is this new body of the Students Council which will, most probably, function in opposition to the Students Union or perhaps the Students Union will be banned I do not know what is ultimately going to be the pattern of the administration You have, first, the Students Union and you have then the Students Council, a separate one It means you will ban the Students Union On the Students Council there will be nominated office bearers and the Students Council will be represented on the Court I think this smacks of lack of democracy Whatever may be the present faults of the Students Union, they have to be given recognition they have to be corrected You cannot bypass the Students Union The idea is to have a puppet body of the Vice Chancellor which is to be represented on the Court Therefore, the healthy aspect of the Act, the good aspect that is, representation to the students on the Court is negated in a considerable measure by creating a new body in opposition to the Students Union and the Students Union will not get representation

Now Sir so far as the non teaching staff is concerned they do not get any representation The teaching staff gets representation That is a good aspect that you have introduced If this is not done on the basis of seniority and the Vice Chancellor goes on appointing heads of department and these heads of department go to the Executive Council and they elect their representatives to the Court, then indirectly it is the Vice Chancellor who will manage to keep his own men on the Court and on the Executive Council This aspect also you have to re-examine

There is another aspect, namely, the character of the University. When we passed the Aligarh Muslim University Bill, I think there was a demand here that representation should be given to all sorts of Muslim organisations. There were some amendment suggested here to that effect. At that time I opposed it. They wanted 40 to 50 people to be brought to the court from all sides to keep a certain balance in the University. I said at that time that representatives of some of these organisations would not be in tune with the character of modern secular educational institutions; they will not be mentally in tune. I now think that nothing will be lost if some of the organisations which are imparting instruction or education in Muslim learning, in Muslim philosophy in Muslim theology or in Arabic and Persian are represented on the court. I think some of these organisations may be given due representation Let them be there. No Heavens will fall if some of them are given representation to create a sense of confidence among Muslims. I do not want them to be given very big representation because that is not in tune with the whole development that is taking place. Therefore, I will suggest that in the composition of the Court you should consider this question of giving representation to some of the Muslim educational institutions. I do not want representation to be given, for example, to what is called the Momin Biradari or any Biradari, as was suggested earlier. There was a suggestion that it should be given representation. I do not take this seriously. But some of the educational institutions like the one from which our Maulana Azad Madni comes should be given representation It is doing good work among the Muslims in the sense that it is promoting their religious and cultural life. Such institutions are part of our life, part of India and part of the reality of the culture of Muslims. So organisations like that can be given representation. Nadwa of Lucknow can be given representation. Some other educational societies may be given representation. But I would not like Auqaf to be given representation. In principle it should also be conceded that Muslim learning should find its place on the court. Educational institutions which are connected with Muslim traditions, Muslim learning, Muslim philosophy, Muslim theology, etc, should also find representation. Then, so far as old boys are concerned, well, it is all right. I do not oppose that. You have given ten members to old boys.

PROF. S. NURUL HASAN: Fifteen.

DR. Z. A. AHMAD: I think it is all right. I am an old boy. There will be other persons Let them come. But regarding donors. I would say, no donors. So, in this way I would like the character of the University to be maintained. I definitely think that the hon. Minister of Education should bear in mind that the traditional character of the Aligarh University has to be maintained in the context of the new secular education developing in our country. So when you nominate or select people, you should take care to see that the composition of the court is such that it inspires confidence. I do not want that this university should settle down to the communal ratio or the population ratio of 8:92. No. It has to be nursed as a specific institution with its own specific historical character. If there is a clear-cut understanding on that point, I think the Prime Minister or the Education Minister can state that. Also in the governance of the university, it should be borne in mind that the internal democracy and autonomous functioning of the university has to be strengthened and due amendments have to be made in its structure.

Lastly I would make an appeal to the hon Minister I am sure he is applying his mind to this question. I am sure he has already some changes in mind. Regarding what the procedure should be, he may say that the amendments cannot be brought here, that the teaching staff can sit and decide. But I think it will have greater political impact if the amendments are brought here. You can sit in closed rooms and come to some understanding. But let it be clearly put before the two Houses; let a statement be made

[Dr. Z. A. Ahmad.]

that in view of the fact that there are certain misunderstandings, we want to clarify certain things, that we do not want to abolish the traditional character of this university and that we will maintain the character in the modern setting, and to that end amend the present Act.

Lastly I want to say a few words about Jamia. I think something should be done about the Jamia. It is not university according to the definition of university. What is it? It is a hybrid institution. Historically *it has become a hybrid thing.* Jamia should have its role in the field of higher learning. What specific role are you going to give it? I think you are not clear as to what role it will play. It is supposed to be under the Centre. The UGC does not come in yet. It is now proposed to bring if under the UGC. I think that will be good and I suggest that Jamia should be developed as a centre of Urdu learning. After all, Urdu is a language of India It is not a language of Pakistan. We want a place where Urdu gets due recognition and gets scope for its development, where research work can be carried on in Urdu literature.

Jamia should be recognised as a centre of Urdu learning and research. And I would be glad if that specific role is assigned to Jamia. Let Jamia be brought under the UGC and let it be treated like any other University. And let it be properly run and not in an ad hoc manner. You have a representative sitting there with no fixed Budget, you go on changing the Budget from year to year, and that representative sitting there as an overlord and doing all type of wire-pulling. No. I want it to be properly run with this role that it is recognised as a seat of Urdu learning and research. That is what I have to say I hope the hon. Minister will give due attention to whatever I have said and accept my requests.

شری ایم۔ اسعد مدنی (اتر پردیش) :

وائس چیرمین صاحب۔ ایجوکیشن اور تعلیم کسی بھی ملک اور قوم کے لئے ایک بنیادی طاقت ہے ۔ اس سے ملک کے بسنے والوں کا ذہن او ضمیر بنتا ہے اور انکے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس سے ملک بڑھتا ہے طاقت پیدا ہوتی ہے اور روشنی آتی ہے ۔ اس لئے وزارت تعلیم ۔ ایجوکیشن منسٹری۔ ملک کی اہم ترین منسٹری ہے اور اگر کسی ملک میں اس منسٹری میں اندھیرا داخل ہو جائے تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ یہ بہت بھیانک مستقبل کی نشان دھی کرتی ہے۔

آج ہمارے طلبا میں جس طرح کی انارکی ۔ لوٹ مار کا روزانہ تشدد جلا دینا پھونک دینا شراب اور نشہ ان برائیوں کی افراط اور بہتات لڑکیوں کو چھیڑنا۔ مسافروں کا باعزت سفر کرنا مشکل ہو جانا کوئی قانون مشکل سے نظر آتا ہے۔ کیا اس کا حشر ہونے والا ہے۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام کیسا کیریکٹر اور ذہن پیدا کر رہا ہے۔ کہاں ہم جائیں گے۔ اس ظرف خدا جانے ہماری منسٹری کو توجہ ہے یا نہیں۔ پریشانی ہے یا نہیں۔ لیکن

لے جائیں گے۔ اس لئے وزارت کو ایسی تعلیم دینے والی کتابوں کو جرم قرار دینا چاہئے اور اس قسم کے لٹریچر کو روکا جائے۔

میرے سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا۔ میں بھی تقریباً اس سلسلہ میں بائنڈ کرتا ہوں زوردار الفاظ میں۔ ہم لوگ کمیونلزم کے مخالف رہے اور اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ مصیبتیں اٹھائیں لیکن جو صورت حال پچھلے اکٹ میں جو ابھی جاری ہے علی گڑھ کے ساتھ کی گئی ہے وہ بہت نامناسب ہیں۔ نہ اس میں کوئی ڈیموکریسی باقی رہی ہے نہ کوئی اٹونامی باقی رہی ہے۔ اگر یہی تو آج تک کورٹ کیوں نہیں گئے۔ وہاں کام کیوں نہیں ہوا۔ وہاں کوئی نمائندگی نہیں دی گئی۔ ایک ایسی ایسوسیشن کو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جس نے اس کی بنیاد رکھی جس نے برطانیہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کیا۔ اس کو ملک کو بہت دکھ اور پریشانی ہے۔ نہ کہیں صلاحیت نظر آتی ہے نہ اخلاق معلوم ہوتا ہے اور خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے جو کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ نیشنل انٹیگریشن کے خلاف بہت سی کتابیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں۔ انگریزوں کی سازش سے جھوٹی لکھی ہوئی کتابیں جن سے اس ملک کے بسنے والوں کو ہمیشہ لڑائی جھگڑا تنگ نظری کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے وہ آج تک پڑھائی جا رہی ہیں اور پورے ملک میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ آزادی کے اتنے برسوں کے بعد بھی۔ ہماری منسٹری اتنا اہم بنیادی کام بھی نہیں کر سکی۔ اگر ہمارے اسکول ہمارے بچوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی کے نام پر انسان کی طرح دیکھنے کا قابل نہ چھوڑیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا۔ بدگمانیوں اور دشمنیوں میں پلا کر دیں تو ان اداروں کو کیا کریں۔

یہ ہمارے ملک کو جہنم میں

اس میں ہمارے غیرمسلم بھائی بہت بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں بہت سے کچھ لوگ غلط بھی نکلے ہونگے۔ لیکن وہاں سے ڈاکٹر ذاکر حسین اور رفیع احمد قدوائی جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خود ڈاکٹر صاحب وہاں پیدا ہوئے۔ تمام ملک کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ادارہ سے چونکہ جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے اس لئے اس کو کھرچ کر پھینک دینے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی جمہوری کردار رہے نہ تاریخی کردار رہے۔ سب ختم ہو گئے اور وہاں پارٹی کے وقار کو دھکا لگا۔ ہوئے تم دوست جسکے دشمن اسکا آسماں کیوں ہو۔ ۱۹۵۱ کا ایکٹ پنڈت نہرو کی قیادت میں مولانا آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور اس طرح کے قومی رہنماؤں نے بیٹھ کر بنایا تھا ہو سکتا تھا اس کو معمولی ترمیموں سے نافذ کر دیا جاتا اور تمام جھنجٹوں سے نکل جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا۔

بھی نمائندگی آپ نے اس میں نہیں دی۔ اس طرح سے آج وہاں کے طلبا سب کے سب بیزار ہیں۔ وہاں کے پڑھانے والے ان کی اکثریت بیزار ہے۔ جو نہ پڑھانے والا اسٹاف ہے اس کی بھی اکثریت بیزار ہے۔ پولیس کے بی۔ اے۔ سی کے بل پر آپ نے وہاں حکومت قائم رکھی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں نہ کوئی کمیٹی بنی نہ ایگزیکٹیو کونسل کچھ نہیں بن سکا۔ اس طریقہ سے آپ جمہوریت کی جڑ ختم کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایکٹ اسے ہی آسان ہے انرا ہے۔ دودھ جیسا دھلا ہے تو کیوں نکالنے ہو رہی ہے۔ اس سلطنت کو تمام ملک میں باغ و بہار بنانا چاہئے تھا۔ کیا ہماری ایجوکیشن منسٹری کو ہمت ہے اس بات کی۔ دو کیا تاریخی اعلان کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ دھوبی سے جیتے نہ گدھے کے کان اینٹھے۔ یہ صورت حال نہیں ہونی چاہئے۔ معاف کیجئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔

اس طریقہ سے میں اتنی بات اور بھی عرض کرونگا کہ بہت سے ایسے ادارے ھیں جیسے بنارس کا ادارہ ھے یا گوروکل کانگڑی جن کی سندوں کو آزادی کے بعد مانا گیا ھے۔ حالات کا یہ تقاضہ ھے کہ وزارت تعلیم دارالعلوم دیوبند اور ایسے ھی جو دوسرے ادارے ھیں ان کی سندوں کو منظور کرے۔ ملک میں ایسے بہت سے ادارے ھیں جن کی سندوں کو آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد اسٹیٹ نے مانا ھے۔ اس لئے منسٹری اس مسئلہ پر غور کرکے مناسب اقدام کرے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ھوگا۔

اس منسٹری میں ایک آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ بھی ھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ھے کہ یہ آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ کیا چیز ھے۔ یہ تاریخی اھمیت رکھنے والی نوادر کی حفاظت کرنا مقصود ھے یا ان کو بگاڑنا مقصود ھے۔ آپ کہتے ھیں کہ حفاظت کرنا مقصود ھے لیکن جہاں تک ھماری معلومات ھیں واقعات اس کے بالکل برعکس ھیں۔ ھم نے الور اور بھرت پور میں معلوم کیا کہ وھاں پر مسجدوں مدرسوں اور درگاھوں کو توڑ پھوڑ کرکے اسکول بنا لیا گیا۔ کھڑا گھر بنا لیا گیا اور کہیں مندر بنا لیا گیا اور آپ کا ڈیپارٹمنٹ بالکل خاموش ھے۔ یہیں دھلی میں قدسیہ بیگم کی مسجد میں ۱۹۴۷ تک نماز جماعت کا انتظام تھا اور وھاں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی لیکن ۱۹۴۷ کے بعد گڑبڑی ھوگئی اور وہ انتظام نہیں رھا اس کے لئے ھم برسوں سے کوشش کر رھے ھیں۔ وھاں ایک بس اسٹینڈ بن گیا ھے اور بس اسٹینڈ بن جانے کی وجہ سے جو ھزاروں مسلمان وھاں آتے ھیں وہ اس کی ویرانگی کو دیکھتے ھیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے ھیں کہ وہ کس طرح سے خراب حالت میں پڑی ھوئی ھے۔ اس میں کبھی کوئی جانور گھس جاتا ھے کبھی کوئی چلا جاتا ھے۔

श्री महावीर त्यागी : यह कहा है।

شری ایم۔ اسعد مدنی : یہیں دھلی میں کشمیری گیٹ کی طرف ھے۔

श्री महावीर त्यागी : उस जगह का नाम क्या है।

شری ایم۔ اسعد مدنی : مسلسل

مسجد میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں کبھی کوئی گدھا گھس جاتا ہے کبھی کتا گھس جاتا ہے۔ ہم اس میں نماز کی اجازت چاہتے ہیں اور اس کے لئے بار بار درخواست کی گئی لیکن آپ کا آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہاں نماز پڑھنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ اس بات کی گواہ ہیں کہ وہاں نماز پڑھی جا چکی ہے۔ لیکن وہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔

اس طرح سے اردو بورڈ کا مسئلہ ہے۔ سنا ہے کہ اس پلان میں ایک کروڑ روپیہ اس کے لئے رکھا گیا تھا۔ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم کو یہ ضرور خطرہ ہے کہ شاید آدھی سے زیادہ رقم لیپس ہو جائے گی اور کہنے کے لئے ہو جائے گا کہ ہم نے تو رقم رکھی تھی۔ اس سلسلہ میں جو صورت حال وزارت تعلیم کی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس صورت حال کو بدلنا چاہئے اور روشنی آنی چاہئے اور اگر روشنی نہیں آتی ہے تو کم سے کم اندھیرا نہیں آنا چاہئے۔ اگر اندھیرا وزارت تعلیم پھیلائے گی تو ملک میں کہاں سے روشنی آئیگی۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس اندھیرا کو بدل کر اس کی جگہ روشنی پھیلائی جائے۔ ملک میں جن باتوں سے بے اطمینانی ہو سکتی ہے تو ان کی طرف توجہ دلانا ہمارا فرض ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی اصلاح کی جائیگی کیوں کہ ملک کا سارا مستقبل وزارت تعلیم کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔

جن باتوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ان کے بارے میں اگر ریکارڈ کی ضرورت ہوگی تو میں اس کو پیش کرنے کے لئے تیار ہوں۔ ان مجمل الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج جو موجودہ رخ ہے اس کو وزارت تعلیم بدلے گی۔

†[**श्री एम० असअद मदनी** (उत्तर प्रदेश) : वाइस चैयरमेन साहब । एजूकेशन और तालीम किसी भी मुल्क और कोम के लिये एक बुनियादी ताकत है। इससे मुल्क के बसने वालो का ज़हन और जमीर बनता है और उनके मुस्तकबिल की तामीर होती है, इसी से मुल्क बढ़ता है, ताकत पैदा होती है और रोशनी आती है। इसलिये वजारत तालीम एजूकेशन मिनिस्ट्री मुल्क की अहमतरीन मिनिस्ट्री है और अगर किसी मुल्क मे इस मिनिस्ट्री मे अधेरा दाखिल हो जाये तो फिर उस मुल्क का क्या हशर होगा? यह बहुत भयानक मुस्तकबिल की निशानदेही करती है।

आज हमारे तुलबा मे जिस तरह की अनारकी, लूटमार का रोजाना तशदद जला देना, फूक देना शराब और नशा इन बुराइयो की अफरात बहुतायत लड़कियो को छेड़ना, मुसाफिरो का बाइज्जत सफर करना मुश्किल हो जाना, कोई कानून मुश्किल से नजर आता है। क्या इसका हशर होने वाला है, हमारे मुल्क का तालीमी नजाम कैसा करेक्टर और जहन पैदा कर रहा है, कहा हम जायेगे। इस तरफ खुदा जाने हमारी मिनिस्ट्री को तवज्जोह है या नही, परेशानी है या नही। लेकिन मुल्क को बहुत दु ख और परेशानी है। न कही सलायत नजर आती है न अखलाक मालूम होता है और खराबिया बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से जो किताबे स्कूलो मे पढाई जा रही है उनमे बहुत सी खराबिया है—नेशनल इटेग्रेशन के खिलाफ बहुत सी किताबें पूरे मुल्क में फैली हुई है और पढ़ाई जा रही है। अग्रेजो की साज़िश से झूठी लिखी हुई किताब जिनसे इस मुल्क के बसने वालो को नफरत, लड़ाई झगड़ा, तुनक नजरी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है वे आज तक पढ़ाई जा रही है और पूरे मुल्क में पढाई जा रही है, आजादी के इतने बरसो के बाद भी। हमारी मिनिस्ट्री इतना अहम बुनियादी काम भी नही कर सकी। अगर हमारे स्कूल हमारे बच्चो को हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी के नाम पर इन्सान की तरह देखने के काबिल न छोड़े और आपस मे लड़ाई झगड़ा, बदगुमानिया और दुश्मनियो मे मुबतला कर दे तो उन अदारो का क्या करे। ये हमारे मुल्क को जहन्नुम मे ले जायेगे। इसलिए वजारत को ऐसी तालीम देने वाली किताबे को जुर्म-करार देना चाहिए और इस किस्म के लिट्रेचर को रोका जाये।

मेरे से पहले अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के बारे मे डाक्टर साहब ने बहुत कुछ कह दिया मे भी तकरीबन इस सिलसिले मे ताईद करता हू जोरदार अलफाज मे। हम लोग कम्युनिलिज्म के मुखालिफ रहे और अपनी कौम का मुकाबला किया, मुसीबते उठाई लेकिन जो सूरत हाल पिछले एकट मे जो अभी जार है अलीगढ़ के साथ की गई है वह बहुत नामुनासिब है। न इसमे कोई डेमोक्रेसी बाकी रही है न कोई आटोनामी बाकी रही है। अगर थी तो आज तक कोर्ट क्यो नही बनी? वहा काम क्यो नही हुआ? वहा कोई नुमायदगी नही दी गई। एक ऐसी एसोसियेशन को मुस्लिम येजूकेशनल कानफ्रेस जिसने इसकी बुनियाद रखी जिसने बरतानिया गवर्नमेट और गवर्नमेट आफ इण्डिया से मुतालबा किया। इसको भी नुमाइन्दगी आपने इसमे नही दी इसी तरह से आज वहा के तुलना सब के सब बेजार है। जो न पढ़ाने वाला स्टाफ है उसकी भी अक्सरियत बेजार है। पुलिस के पी-ए-सी के बिल पर आपने वहा हकूमत कर रखी है इसका नतीजा है कि वहा न कोई कमेटी बनी न एग्जीक्युटिव काउसिल

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री एम० असअद मदनी]

कुछ नही बन सकी इस तरीके से अगर जमहूरियत की इज्जत खत्म कर दी। मै कहता हू कि अगर यह एक्ट ऐसे ही आसमान से उतरा है, दूध जैसा धुला है तो क्यो तकलीफ हो रही है इस सलतनत को तमाम मुल्क मे बाग व बहार बनाना चाहिए था। क्या हमारी एजूकेशन मिनिस्ट्री को हिम्मत है इस बात की। तो क्या तारीखी एलान करने के बावजूद वह कुछ नही कर पा रही है। धोबी से जीते न गधे के कान एठे। यह सूरतहाल नही होनी चाहिए। माफ कीजिये—अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से मुसलमानो का कोई मसला हल होने वाला नही है। इसमे हमारे गैर-मुस्लिम भाई बहुत बड़ी तादाद मे पढ़ते है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मे बहुत से कुछ लोग गलत भी निकले होंगे लेकिन वहा से डाक्टर जाकिर हुसैन और रफी अहमद किदवई जैसे लोग भी पैदा हुए है। खुद डाक्टर साहब वहां पैदा हुए। तमाम मुल्क की यूनिवर्सिटियो मे हजारो मुसलमान भी पढ़ रहे है। लेकिन एक अदारा से चूकि जजबाती लगाव हो गया है इसलिये इसको खुर्च कर फेंक दे यह मसला हल होने वाला नही है। न कोई जम्हूरी करदार रहे न तारीखी करदार रहे। सब खत्म हो गये और वहां पार्टी के वकार को धक्का लगा। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यो हो। 1951 का एक्ट पडित नेहरू की कैयादत मे मौलाना आजाद डा० जाकिर हुसैन और इसी तरह के कौमी रहनुमाओ ने बैठ कर बनाया था। हो सकता था इसीको मामूली तरमीमो से नाफज़ कर दिया जाता और तमाम झंझटो से निकल जाते लेकिन ऐसा नही हुआ।

इसी तरीके से मै इतनी बात और भी अर्ज करूगा कि बहुत से ऐसे अदारे है जैसे बनारस का अदारा है या गुरुकुल कागडी जिनकी सनदो को आजादी के बाद माना गया है। हालात का यह तकाजा है कि बजारते तालीम दारूल उलूम देवबद और ऐसे ही जो दूसरे अदारे है उनकी सनदो को मजूर करे। मुल्क मे ऐसे बहुत से अदारे है जिनकी सनदो को आजादी के पहले और आजादी के बाद स्टेट ने माना है। इसलिए मिनिस्ट्री इस मसला पर गौर करके मुनासिब अकदाम करे। इससे बहुत से लोगो को फायदा होगा।

इस मिनिस्ट्री मे एक आरक्योलाजीकल डिपार्टमेंट भी है। मेरी समझ मे नही आता है कि यह आरक्योलाजीकल डिपार्टमेंट क्या चीज है? तारीखी अहमीयत रखने नवादर की हिफाज़त करना मकसूद है या इनको बिगाड़ना मकसूद है। आप कहते है कि हिफाजत करना मकसूद है लेकिन जहा तक हमारी मालूमात है वाक्यात इसके बिल्कुल बरक्स है। हमने अलवर और भरतपुर मे मालूम किया कि वहां पर मस्जिदो, मदरसो और दरगाहो को तोड़ फोड़ करके स्कूल बना लिया गया। कूड़ा घर बना लिया गया और कही कहीं मन्दिर बना लिया गया और आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है। यहीं दिल्ली मे कुदसीया बेगम की मस्जिद मे 1947 तक नमाज जमायत का इंतजाम था और वहा किसी किस्म की पाबदी नही थी लेकिन 1947 के बाद गड़बड़ी हो गई और वह इतजाम नहीं रहा। इसके लिये हम बरसों से कोशिश कर रहे है। वहा एक बस स्टेड बन गया है और बस स्टेड बन जाने की वजह से जो हजारो मुसलमान वहां आते है वे इसकी वीरानगी को देखते हैं और वे यह भी देखते है कि यह किस तरह से खराब हालत मे पड़ी हुई है।

इसमे कभी कोई जानवर घुस जाता है कभी कोई चला जाता है।

श्री महावीर त्यागी यह कहा है?

श्री एम० असअद मदनी यही दिल्ली मे कश्मीरी गेट की तरफ है।

श्री महावीर त्यागी उस जगह का नाम क्या है?

श्री एम० असअद मदनी मै कुदसीया मस्जिद कह रहा हू, तो इसमे कभी कोई गधा घुस जाता है, कभी कुत्ता घुस जाता है। हम इसमे नमाज की इजाजत चाहते है और इसके लिये बार बार दरख्वास्त की गई लेकिन आपका आरक्योलाजीकल डिपार्टमेट यह कहता है कि हमारे पास वहा नमाज पढने का कोई रिकार्ड नही है। हजारो लोग इस बात के गवाह है कि वहा नमाज पढी जा चुकी है लेकिन वे लोग इससे इकार करते है।

इस तरह से उर्दू बोर्ड का मसला है। सुना है कि इस प्लान मे एक करोड रुपया इसके लिये रखा गया था। क्या काम हो रहा है क्या नही हो रहा है यह हमे मालूम नही है। हमको यह जरूर खतरा है कि शायद आधी से ज्यादा रकम लेप्स हो जायेगी और कहने के लिये हो जायेगा कि हमने तो रकम रखी थी। इस सिलसिले मे जो सूरतहाल वजारत तालीम की है वह बहुत ही अफसोसनाक है। इस सूरतहाल को बदलना चाहिये और रोशनी आनी चाहिए और अगर रोशनी नही आती है तो कम से कम अन्धेरा नही आना चाहिए। अगर अन्धेरा वजारत तालीम फैलायेगी तो मुल्क में कहा से रोशनी आयेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि इस अन्धेरे को बदल कर इसकी जगह रोशनी फैलाई जाये। मुल्क में जिन बातो से बेइनमिनानी हो सकती है तो उनकी तरफ तवज्जह दिलाना हमारा फर्ज है। बैहरहाल मै उम्मीद करता हू कि इन कमजोरियो को ठीक करने की कोशिश की जायेगी अमलाह की जायेगी क्योकि मुल्क का सारा मुस्तकबिल वजारत तालीम के सही होने पर मौकूफ है।

जिन बातो की तरफ मैंने तवज्जह दिलाई उनके बारे मे अगर रिकार्ड की जरूरत होगी तो मै इसको पेश करने के लिये तैयार हू। इन मुजमिल अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हू और उम्मीद करता हू कि आज जो मौजूदा रुख है इसको वजारत तालीम बदलेगी।

SHRI M RUTHNASWAMY (Tamil Nadu) Mr Vice Chairman, Sir, may I begin by wondering why the Department of Education and Social Welfare over which the honourable Minister of Education so genially preside, is called the Department of Education and Social Welfare when I see very few items of social welfare within his jurisdiction It is only according to this Report, reporting the activities

PROF S NURUL HASAN Sir I would like to make one correction The document that the honourable Member is referring to is the Report of the Department of Education and the Department of Culture The Report of the Department of Social Welfare is of light blue colour and this has also been supplied to all the honourable Members Apparently, he has not got it

SHRI M RUTHNASWAMY I am saying that the Ministry is called the Ministry of Education and Social Welfare

PROF S NURUL HASAN We have brought our Report in two volumes

SHRI M RUTHNASWAMY There are two items of social welfare mentioned in this report, namely, youth welfare and sports and adult education

[Ref. M. Ruthnaswamy.]

Adult education is no doubt a very important factor in social welfare. But the progress made in adult education is very halting and hesitating in this country. When you see that twenty years after independence only 30% of the people are literate and the rate of growth of literacy is only one per cent per year, you can realise how backward adult education is. A new device has been found and it is what is called functional literacy. One would think that it is a new discovery of the Education Ministry. But every system effective education has to take into account the function, the environment and the background of the people who are to be made literate. Thus the agricultural community would be educated from the standpoint of and taking into account the background of the farmers, the cultivators and the farm labourers who are engaged in agriculture. But let us see what the growth of functional literacy has been. So far, about 80 districts have been taken into account in this movement and this Report promises that another 20 districts will be brought under this scheme in the coming year and the annual output of this functional literacy movement is one hundred and eighty thousand per year. At this rate, in view of the fact that the farming population, not only the farmers, but also the lease-holders and the farm labourers, constitute about 100 million of our population, it will take nearly a hundred years for this functional literacy scheme to bring about the literacy of even the farming population. So, a more vigorous system has to be discovered and one has been brought to the notice of the Ministry of Education and that is the Venkata Rao method of making adult people literate. This method has been invented by a veteran worker in the adult education field and it is claimed that it will make an adult literate within a space of three months at a cost of Rs. 20 per head.

I am very glad and am thankful to the Ministry of Education for making the first step towards the encouragement of this method. Recently, the Ministry of Education, under his leadership, has sanctioned a certain amount of money to be supplemented by the Government of Andhra Pradesh. Now, Mr. Venkata Rao has gone to the district of Nizamabad in Andhra Pradesh and has begun his work. At least I am looking forward to the results of that movement. That movement is successful. I would recommend this method most enthusiastically to the Minister of Education and his Ministry.

The other social welfare, with which this Ministry is connected, is the youth welfare and sports. This is very properly within the jurisdiction of the Ministry of Education. In connection with sports, I would like to bring to the notice of the Minister of Education the fact that there has been a kind of scandal recently in the appointment of the new manager who accompanied the Indian Hockey Team to take part in international movements. The gentleman who has been associated as manager with the Indian Hockey Team for years, was substituted by a police officer. Now, how the morale of the hockey team can be sustained abroad with a new officer being appointed just on the eve of its departure from India? I hope the Minister of Education will look into this matter and right the wrong if it has been committed.

These are the few remarks that I would like to make, Mr. Vice-Chairman, and I hope that the recommendations that I have made in this short speech will be sympathetically considered by the Minister to be able to take the steps that are necessary to encourage this movement of adult literacy, because that is the foundation of political and social progress. Unless the people are literate, how are they going to become progressive not only in the field of economy but also in the field of social progress?

I hope and trust that the Minister will take up this movement of adult literacy as one of the chief movements with which his Ministry will be concerned during the term of his office.

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR ADIVAREKAR (Maharashtra): Mr. Vice Chairman, Sir, many of the hon. Members have spoken more on the educational aspect, but I would like to deal with the social welfare aspect of the Ministry.

Although the Social Welfare Ministry can take justifiable satisfaction in the extremely good work it has done in the last more

than 20 years, we still feel that the Ministry will have to again gear itself up to play an important role in the 5th Plan period. The Department will now have to promote many new activities to meet the challenges of the seventies. If we fail to do so, it means we are still less aware of the ramifications and intricacies of these challenges.

The system of social welfare services which has been achieved till today is good by the standard of its time, but it is not at all comprehensive and adequate to meet the multifarious problems and needs of the society. This system has grown up at different speeds and with different patterns. The impetus came either from some pressing need or some visionary idea, rather than a set plan. But, Sir, now we will have to work to achieve a balanced economic growth and social justice for the society. The Ministry will definitely play a key role in making people ready to accept the new technology, new science and even the new way of life without making them lose their feet off the ground. And in order to achieve that, the machinery to reach the remotest villages and backward and weaker section of people will have to be evolved. The network of social welfare boards all over the country will have to be remodelled. It should work as a dynamic agency to meet the social needs. It just cannot be a meeting point for worker and community, but it must be a strong force which can weld them together, which can integrate them together for national integrity and progress. Social work methods must adjust to developing philosophies of social work and also to changing professional knowledge and skills. In this regard, case work should be given the highest importance. In solving the problems of the weaker sections of the society who constitute the majority in the country.

The concept of social work and methods are not static, as they continuously develop. Social work, Sir, can really supply a field laboratory and it can tremendously help in breaking down the class distinctions and help in establishing certain standards and values. But it requires coordination and cooperation at all levels. To give an example, Sir, I would like to draw attention to one or two cases. What happened to the Bulsara Committee Field Counselling Service to help and guide voluntary organisations? What is the future of condense courses for self-employment for economically handicapped people and whether any evaluation of such scheme has been done to find out whether it has served any purpose?

It is an accepted fact that evaluation is a scientific investigation to judge the efficiency of a programme in terms of its objectives and achievements. Do we do that? Help for people's individual and personal difficulties call for expert skills, especially in a welfare state. Have we tried to make available such expert knowledge and skill for the use of the agencies who require it? Related to this is the practice and training of social welfare workers. As the functions and problems have differentiated and multiplied, it is very necessary to provide this facility. The very purpose of social welfare services is to make them available in an effective way to the society. It is a well-accepted fact that along with the Government Agencies, the private voluntary agencies are indispensable to work in this field. The time has come now that not only we have to extent these services immensely, but we have to execute them skillfully. And this requires more social workers and a continuous effort to increase their potential competence and then alone the organised social welfare work will be elevated to a position of great importance.

Efforts will have to be made to achieve greater effectiveness through periodic reappraisal and reformulation of guiding principles. The field of social welfare is undergoing a continuous development and diversification into specialized areas. Thus Research has become a recognised part of our social endeavours.

The Indian society is being churned from the bottom. A small humble villager also aspires to be something. Life everywhere is on the move. In such a critical time, every individual needs some help. He is to be made aware and conscious of the sacrifices and adjustments he has to make for the betterment of the society. I may be permitted to cite an instance. As part of the Gandhi Centenary Programme, the Maharashtra Government had announced special prizes to villages doing outstanding

[Shrimati Sushila Shankar Adivarekar]

social work More than 5 000 villages participated in the competition Out of them five villages were awarded different prizes I visited some of these villages to understand the motivation behind them progress I realised the importance of highly stimulated social action Is it not possible that 5 lakh and odd villages in our country could be made to feel that they also have a task to fulfil and face the challenges of modernisation Can we not build up an appropriate mechanism for motivating people to act together for their social upliftment Let farming and productive activities get dovetailed into the social and human side of life Today most of the programmes are stereotyped working with the same slow tempo They benefit the richer sections among the backward people and the less fortunate are left out of the pale This will require new programming and a change in the attitudes of the Social Welfare Ministry Is it too much to expect the Social Welfare Ministry to devise ways and means to bring in this new transformation with all the rich experience that they have of more than two decades And I am more than confident that the Social Welfare Ministry will recast its approach to the problems that we are facing today rather than carry on its activities with the same old policy

Sir I sincerely feel that the time has come when social welfare is given the maximum importance in order to achieve our twin objectives of eradicating poverty and fighting social injustice

Thank you

SHRI G A APPAN (Tamil Nadu) Mr Vice Chairman Sir you might remember that Prof Nurul Hasan's appointment as a Minister of Education was announced when we were not in session I was one of the very very few believe it or not that took the greatest interest pride and happiness in this appointment

SHRI M RUTHNASWAMY Why do you say very few

SHRI G A APPAN Whatever it is that is what I feel You might also be aware that when his budget was discussed for the first time I paid great ovation and encomium Not only myself but there were others also who were happy over it But having my hats off for his proficiency in the field of education from the performance that I have seen in him as a Minister I am pained to see that whatever we spoke on the floor of the House to guide him or just to tell our own experience—not to guide him because he is a very highly educated person—our experiences our views our suggestions were not properly heeded to Some of the views I beg to point out here

Everyone's mother tongue is sacred to him it is dear to him to her is well In the field of education one could understand things better and get better education if it is through one's own mother tongue Nobody can deny it and if these 14 languages scheduled in the Constitution of India are to be developed my humble view is that each language should be left to its own self For people who are jealous to protect their own mother tongue and to benefit by it should support and work for its improvement at his own cost but not one language to be supported and improved or developed or encouraged at the cost of the other languages I had been a member of the Consultative Committee of Education and Social Services You know the Constitution provides in the Directive Principles of the State policy that education should be free at least up to 14 years of age, at least upto 8th standard if I am not incorrect Everybody wants to develop his own language but on a number of times both on the floor of this House and on the platform of the Consultative Committee I requested the hon Minister to please satisfy the greatest aspiration of not the majority but the minority in the Andaman and Nicobar Islands Mr Vice Chairman I have seen some of his plans He wants to give top priority or very high priority for the development of Urdu within a short span that he has been in the office I do not deny that I do not object to it You can develop any language to any extent be it Hindi Urdu or Bengali But should you not care to give education at least up to the 8th standard for the families in the Andaman and Nicobar Islands Eight or ten times I have made representations I have written to him I have written to the Deputy Minister I have written to the Labour Minister I have written to the Prime Minister In spite of that it

is being tossed about this way and that As a humble worker in the field of education I studied the history of development of education in India from 1911 I did not go beyond that period The educational system that prevailed in India up to 1934 was of a good standard In those days even matriculates occupied very senior positions It may not be a surprise that even matriculates were able to compete successfully for the barristers' entrance examination in London You can understand the standard that was maintained in those days The late Barrister Ethirajulu was an example What about present day education? I have seen a number of M As, even Ph Ds who are not able to draft an application for a good job perfectly, correctly and without any mistake Many I have seen Is it the way our education should be dealt with There should be a uniform system of education a uniform syllabus throughout the country Why this duplication of education in the States as well as at the Centre? Why should there be two departments two institutions looking after education? It is duplication It is a waste of money Some of our friends said that Prof Nurul Hasan should resign Why? After all everybody has his own work and everyone cannot be fit for every job Everyone is a specialist in a particular job or avocation One may be clever in one or two jobs Tell him what he should do for the country and in the interests of the nation Let him do it or leave We are not people like Mrs Indira Gandhi to take him to task if he fails to do it Because he is a Minister we request him We give our suggestions Take any other country If a good thing is spoken immediately it is splashed The man is rewarded The man is decorated and his schemes and policies are implemented *in toto* In India good voices, intelligent peoples voices and suggestions are being heard like a voice in the wilderness I only humbly submit that the various educational authorities have been playing ducks and drakes with the educational progress of the young people in this country It is education that is the foundation for citizenship for democracy and for all progress in the country, *viz*, economic development educational development, social development and what not In the past we did not see these things this much of student unrest this much of teacher unrest and this much of non teacher unrest We have seen it even in the elementary education standard, even at the middle school level and also at the high school level Why? Please pardon me As a teacher I say, I have been a teacher from my early years, I have been a teacher in an elementary school, in a middle school, in a high school and even in the training school But I used to work from six in the morning till very late in the night Teaching is a missionary job it should be taken in a missionary spirit Teaching cannot be taken by a person who loves money, who loves leisure No doubt, teaching has a great leisure provided we are able to do our duty dutifully and utilise the spare time How many of the present day teachers are true to their jobs I say, not many, except in the privately managed schools But lo! this Government wants to curb all the private management schools and aided schools which help not themselves but the Government by running the institutions more effectively in a refined and disciplined way, with better efficiency at half the time, just for a meagre grant, maintenance grant But it wants to give them all hardships It is paying its teachers because they are able to agitate, because they are able to gherao, because they are able to give trouble to the Government But because the private school managers are very poor people, because they are not sufficiently organised they do not care There is a new Education Bill which the hon Minister is going to pilot Of course I have told him Please consult the school managers who have experience But do not try to kill the goose that lays the golden eggs The new Bill that they are going to introduce is nothing but killing the goose that lays the golden egg—not one goose but a number of goose I request the hon Minister to please see that he abandons the Bill or that he gets the concurrence of views of private managements

Sir I entirely agree with Prof Ruthnaswamy's remarks I like them I was doing adult education even with Laubach's Chart I though that I was able to make people literate when I was in my high school career In our days only high school students from the missionary institutions used to take up that work Government did not pay any attention to adult education

[Shri G. V. Appan.]

in those days. When I was in the high school and in the teachers training school, I used to go out during the week-ends and take up adult education courses through Mr. Khaitan and Mr. Lorbeer of Pasumalai, the architect of the Kallar Reclamation scheme and of adult education, stalwarts in those days. I agree with Prof. Ruthnaswamy. The Hyderabad Plan could be done and implemented within three months. A person could be made literate within 3 months within a cost of Rs. 20. I think the cost factor may not be correct. If you want cheap things, it will not be worthwhile. But it is possible to make a person literate within 3 months. At the rate of Rs. 20 a month, it will cost Rs. 60 per head. Let every teacher take 10 people every month or 20 people. So, let us have a band or army of people who will take up adult education as a mission or service; rather than keeping and retaining people upto 60 years you retire people at 55. Let the teachers take to adult education and be paid the same salary. I feel undue encouragement is being given to people with good merit. There is a proposal in the Fifth Five Year Plan for merit scholarship. But many a time these scholarships are given to very rich people. This scholarship is a grant, an aid given to alleviate the sufferings of the parents. A number of officers drawing Rs. 2,000 or Rs. 1,500 per month have come and complained to me that their son gets his scholarship only at the end of March.

SHRI PITAMBER DAS: So that they get it three months in advance?

SHRI G. V. APPAN: No, it is at the end of the year. To whom should the loan scholarship be given? Please do not give any scholarship to anybody who can manage without it. But do give financial assistance to those who want it but not as a dole at the poor man's cost. Let boys who are talented and who want to return the scholarship money be given scholarship. This would be in the interest of the nation, in the larger interest. Let them repay when they get employed. (*Time Bell rings.*) Two minutes. Why do you throw away money on those who do not deserve it? Give loan to them. They will return it when they come back and get employment. When they come here give them maintenance allowance, not Rs. 2,000. Let it be recovered. Our country is not a rich country. Ministers should not dole out money. I entirely agree with Prof. Ruthnaswamy that our education should be job-oriented, preferably agriculture-oriented. India being mainly an agricultural country our education should be agriculture-oriented. What is the use of turning out people aimlessly? What is the cost of turning out a matriculate, turning out a P.U.C., a graduate or a post-graduate and what not? We should have the cost factor in mind and how it is utilised. When a person invests money in thousands he does expect interest from it. Is it not the duty of the Education Ministry to see that the money spent on education should be usefully spent? No doubt it is social service, we entirely agree. But it cannot be frittered away.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): That will do.

SHRI G. V. APPAN: Only two or three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You have already taken more time. We are getting late. There are other speakers also. You have already taken 18 minutes.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: श्रीमन्, पाच बज गये है। अब कल इसको लीजियेगा। पाच बजे से आगे चलाने के लिए न बिज़िनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने कुछ कहा है और न लीडर आफ द हाउस ने कोई अनुरोध किया है।

श्री सीताराम सिंह: श्रीमन्, इसको कल के लिए रखा जाय।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: आज इसको आगे चलाने की क्या आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): आज ही खत्म किया जायगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी बहुत से बोलने वाले है और अभी मत्री महोदय का जवाब होना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): आज ही समाप्त होना है।

श्री महावीर त्यागी : इसके अलावा हाउस मे मत्री महोदय का तब जवाब होना चाहिये जब कि ज्यादा से ज्यादा लोग हो।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हाउस मे कोई है ही नही।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू : आज का बिजिनेस आज ही खत्म करना है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आज अभी बिजिनेस बहुत ह।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): कभी-कभी पाच बजे के पहले भी हाउस ऐडजर्न हो जाता है। परसो पाच बजे के पहले ऐडजर्न हो गया था।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव अभी बहुत से बोलने वाले पडे है जो घटो बोलते है। फिर आज ही समाप्त करने की क्या जरूरत है।

डा० जेड० ए० अहमद : सब थक गये है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : कल के लिए रखियेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) मिनिस्ट्री के बारे मे जब कभी चर्चा हुई है पहले भी तो उसी दिन वह समाप्त हो गयी है। एक घटे ज्यादा बैठने से क्या हो जायगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक घटे मे यह नही होगा।

SHRI RANBIR SINGH (Haryana) Another resolution is coming up on the non official day We can finish the discussion now The Minister can reply to morrow

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अभी बहुत से बोलने वाले है। समय नही है तो क्या जरूरत है । किसी भी कीमत पर यह आज समाप्त नही हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : यह बिजनेस एडवाइजरी कमटी मे भी

SHRI A G KULKARNI We have to complete the work to day

SHRI OM MEHTA It has been decided already One day is always given for this purpose

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पाच बजे के बाद फिर क्यो बैठ रहे है?

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : इसमे खास बात यह हे कि इस को पाच बजे के पहले खत्म हो जाना चाहिए था। एजेडा पर कम स्पीकस थे, लेकिन अधिक स्पीकर्स को मौका दिया गया यह सोच कर कि कुछ ज्यादा देर तक बैठ जायेगे। Let us not break the tradition

SHRI OM MEHTA We are prepared to close the discussion if they are not interested in the reply

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) Yes, Mr Barbora

SHRI G V APPAN Only two more points Sir I have taken only ten minutes

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) No you have taken 18 minutes

SHRI G V APPAN Only two more points.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) All right, you can take two minutes more.

SHRI G V APPAN Mr Vice Chairman, I have been telling the House and the Government that elementary education is more important for the country than higher education Those who can afford go in for higher education but in elementary education there is no use massing 35 or 40 students in Standard I I request the hon Minister to consider this very important suggestion In Standard I and Standard II the strength should not be more than 25 or 30 per class Otherwise it will not be a class, it will be only a gang, and our money will be wasted How can a teacher manage more than 20 or 25 students? At least 70 per cent of the money spent on education should go for elementary education up to Standard VIII He should also see that all children within the school going age are brought to the school If parents do not send their children, we should penalise the parents and bring all children below 14 years of age into the field of education

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) All right, thank you.

SHRI G V APPAN Regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you are not able to admit Scheduled Castes people up to 20 per cent though the Constitution provides for it You should make it a point not to give any grant for any school college or professional institution whether it is under private management or it is a Government institution, unless this quota of 20 per cent for the Scheduled Castes and 7½ per cent for the Scheduled Tribes is fulfilled

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) Now please sit down Mr Barbora

SHRI G V APPAN I hope the hon Minister will be able to do full justice to the salient points that I have raised Thank you

श्री गोलाप बरबोरा (आसाम) : उपसभापति जी, आजादी के 25 साल के बाद भी शिक्षा मत्रालय के सामने न तो कोई दिशा है और न कोई उनका प्लान है। जैसा कि आज सुबह प्रइमरी एजुकेशन के बारे मे एक सवाल के जवाब मे कहा गया था कि 1961 ई० से ले कर 1971 ई० तक जो निरक्षर लोगो की सख्या इस देश मे 333 मिलियन थी, वह 386 मिलियन तक बढ गई। यह हालत है हमारे देश में। और जो शिक्षा मत्रालय ह उसमें न जाने कितनी शाखाये है, समझाना मुश्किल है। तो इसकी वजह क्या है ? वजह यही है कि आप सोचते है पुराने ढ़ग से कि सब जगह स्कूल हो, स्कूल बिल्डिग हो, दो ढाई सौ रुपये महीने की तनख्वाह वाला टीचर हो, तभी आप एलिमेटरी एजुकेशन को स्प्रेड कर पायेगे। यह होना तो असम्भव है और आप जितना भी प्लान करते जायेगे उतना हो इस देश मे, इस मत्रालय के गलत तरीके की वजह से, निरक्षर लोगो की तादाद और बढती जायगी। मेरा यह सुझाव है कि जल्दी से जल्दी देश मे एक शिक्षा सेना दल कायम करना चाहिये, जिसमे एजुकेटेड अन-इम्प्लायड नौजवान हो और उनको कुछ मेनटेनेस एलाउस दिया जाय या कुछ पाकेट मनी दे कर के स्कूल कालेज के विद्यार्थियो को वालटरी काम करने का मौका दिया जाय। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाय करीब पाच लाख लोगो का पाच लाख गावो के लिये। इसके पीछे आपका बहुत ज्यादा रुपया खर्चा नही होगा। तो ऐसा प्रोग्राम ले कर के काम करे। यह प्रोग्राम और देशो मे भी हुआ है, चाइना मे हुआ हे और यूरोप के दूसरे देशो मे हुआ है रूस मे हुआ हे सन् 1917 की क्रान्ति के बाद। आप अगर इसी खयाल मे रहेगे

कि आपका बजट प्राविजन हो, उस बजट में एलिमेंटरी एजुकेशन के लिये कुछ ग्रान्ट हो, हर जगह कम से कम पाच हजार रुपये की एक स्कूल बिल्डिग बनवायें और उसमे पर्मानेन्ट टीचर एप्वाइट करे तो आपका देश मे सभी लोगों को एलिमेंटरी एजुकेशन देने का सपना कभी पूरा नही हो पायेगा।

इसी के साथ-साथ जहां हायर एजुकेशन का सवाल है, वहां चारो तरफ अंधेरा है, कहीं कोई डिसिप्लिन नही है, कही कोई युनिफार्म पालिसी नही है, सेकेंडरी एजुकेशन की वही हालत है, कालेज की वही हालत है और आपकी युनिवर्सिटीज की भी वही हालत है। आपकी सेंट्रल युनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि दिल्ली में सेंट्रल युनिवर्सिटी है। अगर दिल्ली की युनिवर्सिटी सेंट्रल युनिवर्सिटी है तो हर युनिवर्सिटी के आने वाले विद्यार्थियों को यहां मौका मिलना चाहिये लेकिन वह नही मिलता है। जो आसाम के रहने वाले हैं, जो वहां के विद्यार्थी है उनको मौका नही मिलता है। वहां गौहाटी और डिब्रूगढ युनिवर्सिटी है और चूंकि गौहाटी और डिब्रूगढ़ युनिवर्सिटी का रिजल्ट कुछ देर से निकलता है तो जब दिल्ली युनिवर्सिटी मे या यहा जितने कालेज है उनमें जो विद्यार्थी वहां से एडमिशन के लिये आते है तो मीट्स फुल रहती है और उनको एडमिशन नही मिलता है। इसको सेंट्रल युनिवर्सिटी हम तभी मान सकते है जब कि जिस शहर मे वह हो या उसके अगल बगल जो हों उनको ही मौका नही मिले, बल्कि उसमें हर प्रान्त के लोगों को पढने का मौका मिले। तो इसके लिये कोई युनिफार्म पालिसी आपकी होनी चाहिये।

युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हर युनिवर्सिटी को पैसा देता है, हर कालेज को पैसा देता है लेकिन युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रुपये को ले कर—ज्यादातर कांग्रेस के लोग—धांधली मचा रखी है। एक तो ऐसा हो गया है कि पावर मे आने के लिये, इलेक्शन मशीनरी में कुछ कब्जा पाने के लिये, लोकल लीडरशिप में काबू पाने के लिए कोई भी स्टेट मे कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, वह अपना आदमी हर कालेज की गवर्निंग बाडी में रखता है और लोग खा जाते है पैसा।

मैं जिस शहर से आता हूं उसके कालेज का डेढ दो लाख रुपया गायब है, युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का वह रुपया है। वहां एक क्लर्क गए, एक प्रिन्सिपल साहब गए, ठीक है, लेकिन वहां का कांग्रेस का एक नेता था जो आसाम का मिनिस्टर है और एक कभी एम० एल० ए० रहा, वे लोग भी वहां थे। पांच साल तक लगातार कोई आडिट नहीं हुआ और प्रिन्सिपल साहब गए, वहां का कोई पीयन चला गया, एक क्लर्क चला गया, लेकिन जो नेता लोग थे उस गवर्निंग बाडी में, जो चाहे जाने हों, अनजाने हों, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन जहां कालेजों में युनिवर्सिटियों में रुपया देता हो, उस रुपए का इस्तेमाल किस ढंग मे होना है, उस पर भी नज़र होनी चाहिए, और ठीक ढंग मे अगर उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो ऐसे कालेजों में पैसा तब तक नहीं देना चाहिए, जब तक उसके खर्चे का सही इस्तेमाल करने के बारे में कोई रिपोर्ट उनको न मिले।

आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ "यूनिसेफ" "यूनेस्को" आदि सस्थाओं का भी संबंध है। आपको युनाइटेड नेशन्स की संस्थाओं के जरिए करीब 6-7 करोड रुपया आया होगा और उनमें से एक

[श्री गोलाव बरबोरा]

संस्था इन्टरनेशनल कमीशन फार कोआपरेशन विद यूनेस्को भी एक है। उसमें कितने फैलोशिप्स है, कितने कमीशन्स है, ग्रान्ट्स फार फारेन ट्रैवलर्स है। लेकिन हम देखते है—मन्त्री महोदय आप बुरा मत मानिए—ये सब जितने फैलोशिप्स ग्रान्ट्स और कमीशन जो है ये सब आफिसेज बने हुए है दिल्ली के इर्द-गिर्द और यह लोगों के कमाने खाने का और भाई-भतीजावाद बढ़ाने के साधन है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री गोलाप बरबोरा : जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। वही हालत एकेडेमीज की है। वह चाहे संगीत नाटक अकाडमी हो, ललित कला अकाडमी हो, साहित्य कला अकाडमी है। मैं एक पिछड़े हुए प्रदेश का वासी हूं, मेरा चैलेन्ज है कि इन सारी फैलोशिप्स में, सब कमेटियो में, कौसिल्से में, इन्स्टीट्युशन्स में, मेरे प्रान्त से किसी को मौका मिला है, ऐसा मालूम नही पड़ता है। हमारे यहां भी शिक्षित लोग है, हमारे यहां भी स्कालर लोग हैं, उनको क्यों चान्स नहीं मिलता है? या तो कलकत्ता के रीजनल आफिस के इने-गिने लोग या मद्रास के रीजनल आफिस के इने-गिने कुछ लोग भाई-भतीजावाद चलाते है। इसके केसेज आए है। आपके पहले इम्पीरियल गैजेटियर या इम्पीरियल गैजेटियर के बाद नेशनल गैजेटियर में कुछ प्रबन्ध हुआ था, जब हुमायुन कबिर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, सन् 1958 में कोई कमेटी बनी, 4 वाल्यूम निकालने को तय करके एक वाल्यूम कही 1971 में छपा, एक प्रेस में गया, और एक ओई तैयार है, प्रेस में गया नही है, और चौथा अभी तैयार नही है, लाखों रुपए खर्च हुए इन सब पर—आडिटर जनरल का रिमार्क है—तो मै जानना चाहता हूं आप क्या कार्यवाही उस पर कर रहे हैं? वह एक वाल्यूम भी इस ढंग का है कि वहां एक बहुत पुराना जो इम्पीरियल गेजेटियर ब्रिटिश जमाने का रहा उसी को फिर रिप्रिन्ट किया गया। तो नेशनल गेजेटियर बनाने में या डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें लाखों करोड़ों रु० जो बर्बाद करने हैं, उसके ज़रिए काम क्या हुआ या नहीं, इसकी देखभाल करने की भी क्या कभी आप कोशिश करते है? मेरा तो ख़याल है कि इसके ऊपर देखभाल करने वाला कोई है नहीं।

स्पोर्ट्स का ज़िक्र किया गया। ओलम्पिक गेम्स में जो कुछ भी हुआ था देश भर को मालूम है। हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स भी उसी तरह कुछ लोगों के हाथ का एक खिलौना बन गया है, पेशा बन गया है और आप जानते हैं, इस देश की एक बीमारी है, विदेश घूमने के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। ओलम्पिक्स एसोसिएशन में लोग घुस जाते है, जिनका खेल-कूद के साथ कोई संबंध नहीं होता है। सब कोई विदेश जाना चाहते है। अभी जब पार्लियामेन्ट की रीसेस हुई थी तो किसी ने लिखा था—इंडिया इज़ रूल्ड फ्राम एबाड बिकाज़ आलमोस्ट द इन्टायर कैबिनेट इज़ आउट आफ इंडिया। वही मिनिस्टरों की हालत है, वही आफिसरों की हालत है और वही देश के जनसाधारण नागरिकों की हालत है। कलकत्ते के एक लेखक ने अपने उपन्यास में लिखा है कि बहुत से ऐसे हिन्दुस्तानी हमारे देश में आज है जो विदेश जाने के इच्छुक है। और विदेशी ट्रांजिस्टर और दूसरा सामान

पाने के लिए वे अपने देश को भी बेच सकते है। इस तरह की बीमारी हमारे हिन्दुस्तान में है और वही बीमारी एजुकेशन मिनिस्टरी में भी है। कहीं पर उसने के मिशन बना दिये है, कही पर कमेटी बना दी है, कही पर फैलोशिप कायम कर दिया है और एकाडमीज बना दी है। स्पोर्ट में भी इसी तरह की व्यवस्था है और देखने मे यह आया है कि इस देश में सब विभागो में इस तरह की चीज बना दी गई है। इस तरह की जो व्यवस्था और भावना है उसको हमे रोकना चाहिए।

दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट काम्पलेक्स है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस तरह के केवल दिल्ली में ही न हों, बल्कि हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में इस तरह के क्लब होने चाहिएं और हर रीजन में इस तरह के क्लब होने चाहिएं।

आज हिन्दुस्तान के लोगों में यह भावना हो गई है कि पजाब के ही लोग अच्छे हाकी के खिलाड़ी हो सकते है, लेकिन हाकी का सबसे अच्छा खिलाड़ी बिहार का एक आदीवासी निकला है। दिल्ली में हाकी का जो मैच हुआ था उसमें आसाम, (मिज़ोरम), की टीम आई और उनको पंजाब की मशहूर टीम के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें खेल ड्रा रहा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हू इन सब लोगों को मौका बहुत कम मिलता है। आपने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि सब कौसिल में ही फंस जाते है। इस्प्रिन्ट इवैन्ट्स मे नागालैन्ड के नौजवानों, वहां के विद्यार्थियों को भी ट्रेनिंग की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे लोग भी हिन्दुस्तान के और लोगों के मुकाबले मे आ सकें। आज वहां के लोगों को इस तरह के खेलों और स्पोर्ट्स मे हिस्सा लेने का मौका नही मिलता है। आज हमारे देश में विदेशों में घूमने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है और इस प्रवत्ति का असर यह हुआ कि चाहे कोई भी संस्था हो, स्पोर्ट्स की संस्था हो या कोई दूसरी संस्था हो, सब विदेशों में घूमना चाहते है, चाहे उनका उस चीज से कोई सम्बन्ध न हो।

सरकार की ओर से फुटबाल के खेल के लिए लाखों रुपया मिलता है, लेकिन आज हम यह देखते है कि यह खेल भी पहिले के मुकाबले में गिरता जा रहा है। आज हम यह भी देखते है कि हमारे हाकी के खेल का भी स्टैडर्ड गिरता चला जा रहा है और इस तरह से दूसरे खेलो में भी हमारा स्टैन्डर्ड गिर गया है। आज इन संस्थाओं मे भाई-भतीजेवाद की भावना फैल गई है। *(Interruption)* इस तरह की संस्थाओं में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई है। आसाम और जो बार्डर के क्षेत्र है, वहा के लोगों को इन संस्थाओं में जगह नहीं मिलती है और न ही उनको किसी तरह की कोई सहायता मिलती है।

एक चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय गाने की ट्रेनिग के लिए कुछ प्रान्तों में संस्थाएं खोली है। क्या आप राष्ट्रीय गाने को सब प्रान्तों में गवाना नही चाहते हैं? आप को सब प्रान्तों में इस तरह की संस्था खोलनी चाहिए।

इसी तरह मे एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कूलों में मील्स देने की स्कीम है और इसके बैनीफिसियरिज 127.40 लाख लोग ही है। यह स्कीम 19 स्टेटों और यूनियन टैरिटरीज में लागू है, लेकिन आसाम अरुणाचल, मेघालय जैसे स्टेटों में लागू नही है और न ही लिस्ट में इन स्टेटों का नाम है। स्कूल मील्स सब बच्चो को मिलना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि सब देश के बच्चों को न दिया जा सके, परन्तु हर प्रान्त के कुछ जिलों में यह स्कीम तो लागू की जा सकती है।

इसी तरह से आपके यहां प्रान्तीय भाषाओं मे ट्रान्सलेशन करने की और

[श्री गोलाप बरबोरा]

मौलिक पुस्तक छापने की व्यवस्था है । आपने एक नेशनल बुक ट्रस्ट बनाया है और उसके कर्मचारी दिल्ली मे आज भी हड़ताल में है । वहां पर किताबों का ट्रान्सलेशन होता है और इसी तरह से आपने साहित्यिक अकादमी की स्थापना की है । हमारे यहां से लोकसभा के जो सदस्य है वे उसके सदस्य है । वे शासक दल के है । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी ट्रान्सलेशन किया जाता है, किताब छापी जाती है, अनुवाद किया जाता है वह रीजनल लेगवेज मे बहुत कम किया जाता है । आप मौलिक किताबों को तामिल, आसामीज और दूसरी रीजनल भाषाओ मे अनुवाद करवाइये ।

मेरे एक मित्र है आसाम के अजीत कुमार शर्मा, प्रोफेसर, उनको कहा गया था प्लेटो रिपब्लिक का तर्जुमा करने के लिए । उन्होने उसका तर्जुमा करके भेज दिया । फिर यहां से किसी को देखने के लिए भेजा गया, लेकिन फिर भी आज तक वह किताब छपी नही । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट मे आया है कि कई किताबें लेकर बाद में उनको वापस कर देते है । उन्हे क्यो लिया जाता है और फिर बाद में वापस किया जाता है ? इसके पीछे क्या है ?

इन सब चीजो पर मंत्री महोदय जवाब दें और जहा तक हो सके इस अन्याय को रोकने की व्यवस्था करे तो देश मे शिक्षा की भी तरक्की होगी और आम तौर से हिन्दुस्तान आगे बढेगा ।

श्री सीता राम सिंह (बिहार) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुर्दा वही है फकत कफन बदल गया है हकीकत यह है कि अग्रेज तो चले गए लेकिन आज अग्रेजियत अपने देश मे जोर-शोर से बढ़ रही है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : औलाद छोड गए ।

श्री सीता राम सिंह : मुझे पता नहीं है किसकी कौन औलाद है, इसके लिए अनुसधान करना पडेगा । आज इस देश मे कुछ लोग अपने बच्चो को मम्मी और डैडी सिखलाते है, माता और पिता शब्द से उन्हें सख्त नफरत है ।

श्री गोलाप बरबोरा : अपने घर मे अग्रेजी मे बोलते है दिल्ली में ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आपको पता नही है, हसन साहब हिन्दी समिति में अंग्रेजी में बोलते है ।

श्री सीता राम सिंह : यह खासियत है अपने देश की । एक बच्चे पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक खर्च किया जाता है और दूसरी तरफ 26 वर्षों की आजादी के बाद गलत शिक्षा नीति के चलते इस देश में 38 करोड़ 60 लाख अनपढ़ है । एक तरफ सेंट जेवियर जैसे पबलिक स्कूल चल रहे है, दूसरी तरफ बेसिक प्राइमरी स्कूल चल रहे है, जहां धान रोपना, छैती बनाना–इसकी तालीम दी जाती है । एक तरफ शासक वर्ग पैदा किया जाता है और दूसरी तरफ शासित वर्ग पैदा किया जाना है और ढोल पीटा जाता है समाजवाद का । समाजवाद का अर्थ क्या होता है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह नई परिभाषा है ।

श्री सीता राम सिंह : जिस देश मे शिक्षा में भी एकरूपता न हो—आर्थिक विषमता की बात तो दूर रही—उस देश का शासक वर्ग यह ढोल पीटे कि हमारे देश मे समाजवाद आ रहा है, यह जनता के साथ

एक क्रूर मजाक है राष्ट्र के साथ धोखा है, बेईमानी है।

श्री कल्याण चन्द जैसे आपने समाजवाद का नाम लिया और प्रिवी पर्स मे साथ दिया।

श्री सीता राम सिंह प्रिवी पर्स किसने दिया था, यह भी बता दो। प्रिवी पर्स तुम्हारे ही नेता लोगो ने दिया था। हम हमेशा से इस बात के विरोधी थे कि प्रिवी पर्स दिया जाय।

(Interruption)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० वी० राजू) आप बोलिए आपका समय कम है।

श्री सीता राम सिंह श्रीमन्, मैं आपका सरक्षण चाहता हू। ये लोग राक्षसी बहुमत के बल पर मचल रहे है, लेकिन वह दिन भी आने वाला है जब यह नही रहेगा।

श्री कल्याण चन्द वह दिन नही आएगा।

श्री सीता राम सिंह यह दुनिया परिवर्तनशील है, इसको मित्रो याद रखो।

महोदय, इस देश मे जब तक शिक्षा मे एकरूपता नही आयेगी तब तक राष्ट्र नही बन सकता है। महोदय मै मत्री जी से यह आश्वासन चाहूगा कि शिक्षा मे वह ऐसी कोई व्यवस्था करेगे कि चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे भगी की सन्तान हो, शिक्षा एक समान देने की योजना बनायेगे? जब तक ऐसा नही होगा तब तक महोदय मेरा विश्वास है कि देश नही बनेगा, राष्ट्र नही बनेगा क्योकि आज की शिक्षा पद्धति ज्ञान अर्जन के लिए नही है, वह नौकरी के लिए और व्यापार के लिए है।

महोदय, शिक्षा का मतलब होता है सर्वागीण विकास। लेकिन आज इस शिक्षा पद्धति से हो रहा है सर्वनाश। इसलिए मै मत्री जी से आग्रह करता हू कि बुनियादी तौर से शिक्षा नीति मे तब्दीली कर, परिवर्तन करे र उसे जन मुखी बनाये।

दूसरी बात यह कि आर्थिक विषमता के चलते, इस देश म अनेक बच्चे शिक्षा पाने से वचित रह जाते है। सामाजिक विषमता का जहा तक सवाल है आज इस देश मे अनेको ऐसे गाव है जहा स्कूल मे सवर्ण हिन्दू उच्च जाति के बच्चे हरिजन, आदिवासियो के बच्चो को अपने साथ नही बठने देते। उनके साथ बुरा सलूक करते है। उसकी एक मिसाल मै बताना चाहता हू। बिहार के वैशाली जिले मे एक महुआ प्रखड है। वहा के मिडिल स्कूल मे एक हरिजन शिक्षक सवर्ण शिक्षक के गिलास से पानी पी रहा था और उसके मुह से गिलास छीन लिया और मारने की धमकी दी। इतना भयभीत किया गया कि वह हरिजन शिक्षक उस स्कूल से ट्रासफर करवाकर दूसरे स्कूल मे चला गया है। इस घटना की सूचना मैने राज्यपाल को दी, लेकिन आज तक कुछ हो नही सका है और जो उच्च वर्ग के शिक्षा अधिकारी है वह हरिजन शिक्षक को धमकी देते है कि अगर तुम समझौता नही करते हो तो तुमको हम डिसमिस कर देगे, डिस्चार्ज कर देगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव हरिजन मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हो रहा है?

श्री सीताराम सिंह मिनिस्टर तो मुह देखने के लिए है। यह विषमता का सवाल है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि जो हरिजन शिक्षक है उनके साथ इस तरह की घटनाये घटती है तो जो गरीब

[श्री सीताराम सिंह]

हरिजन के बच्चे है उनका क्या होता होगा। आज यह हकीकत हो गई है।

(Interruption)

अन्त मे मैं माननीय मत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हू। मेरा पहला सुझाव यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय साक्षरता सेना का तुरन्त गठन किया जाए। इससे दो फायदे होगे। एक तो जो पढे लिखे लोग बेकार है उनको रोजी भी मिलेगी और दूसरी बात यह कि जो अपने देश मे एक करोड लोग अनपढ है वह साक्षर भी हो जायेगे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि शिक्षा की जो पद्धति है उसमे विद्यार्थियो को छठी या सातवी कक्षा तक पढाई के अनुसार उसके दिमाग की जाच होनी चाहिए और जिस विद्यार्थी को जिस विषय की अभिरुचि हो उसको उसका विशेषज्ञ बनाना चाहिए। उनको दूसरी किताबो का बोझा डालकर उसके माथे पर उनका भार नही डालना चाहिए। तभी कुछ सम्भव कल्याण हो सकता है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव भोजन की व्यवस्था भी कराइये।

श्री सीताराम सिंह महोदय, गाधी जी ने कहा था कि जब तक इस देश मे देशी भाषाओ मे राजकाज नही चलेगा तब तक इस देश की आजादी अधूरी रहेगी। इस देश का शासक वर्ग गाधी जी को अपनी सत्ता के नशे मे भूल गया है।

उप-सभापति (श्री बी० वी० राजू) अब तो हो गया होगा।

(Time bell rings)

श्री सीताराम सिंह श्रीमन्, जहा तक शिक्षा का सवाल है बिल्कुल व्यापारिक ढग से यह शिक्षा चलाई जा रही है। जहा तक पाठ्यपुस्तको का सवाल है आज देखा जाता है कि अच्छे मे अच्छे लेखक की जो किताबें है उनको रद्दी की टोकरी मे फेक दिया जाता है और आज जिन का सम्पर्क, जिनका सम्बन्ध शिक्षा मत्रालय से है वे चाहे जितनी भी घटिया किस्म की किताब लिखे, टेक्सट बुक कमेटी मे उनकी किताब चल जाती है। *(Interruption)* यह सेटर की बात मैं नही कहता। यह पूरे देश की बात है।

मैं मत्री जी से चाहूगा कि जो मैंने एक दो सुझाव रखे है उनके सामने उनपर वे ध्यान दें और शिक्षा को बुनियादी तौर से तब्दील करे क्योकि आज बडे लोगो के लडके पाच सौ सात सौ और एक हजार रुपया माहवार खर्च करते है, लेकिन जो गरीब का बेटा है उसके लिए कौन सा इन्तजाम हो रहा है। 26 वर्ष की आजादी के बाद भी उसके पढने लिखने के लिए कोई इन्तजाम नही है जबकि सविधान मे जो मौलिक अधिकार है उनके अनुसार हर नागरिक बराबर है। यह सविधान में है लेकिन व्यवहार मे इसकी उलटी बात चल रही है।

THE MINISTER OF EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF S NURUL HASAN) Mr Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to express my deep sense of gratitude to the hon Members for the concern that they have shown about various educational matters facing the country Before I take up individual points, I would like to state that I find myself in agreement with most of the suggestions which have been given by the hon Members and, therefore, if I am unable to comment on every point that has been raised, I would not like my hon friends to feel that their valuable suggestions will not be taken due note of I am looking at the clock because I can see that most of my friends are also looking at the clock and, therefore, I shall try to be as brief as possible

Sir the most important point which has been raised in my opinion, is the question of liquidation of illiteracy My

colleague has already made certain observations in the morning and I would not like to repeat those points. But, as he generally indicated, the strategy which the Education Ministry is advocating to the State Governments is that first of all we must ensure that there is 100 per cent enrolment of children in the age group of 6-11 within this Plan period. Secondly, we must ensure that within the Sixth Plan period we are able to cover the other age group of 11-14 so that the Directive Principles are implemented. Then, side by side with this we want to give the next highest priority to the age group 15-25, the young people who should have been given education if the Directive Principles had been implemented by 1960. But unfortunately we were unable to implement this Directive Principle and I do not think there can be any difference of opinion that it is one of the most important of the Directive Principles and it should have been implemented. And, therefore, I can only join my hon. friends here in expressing my deep sense of anguish that we were unable, as a nation, to implement this Directive Principle. It will therefore be the effort of my Ministry in concert with all the State Governments to ensure that this is implemented as soon as possible and, along with this, the age group 15-25 is tackled with a determination so as to make up for the time that we have lost after 1960.

Then, naturally there are other programmes of literacy, for adults. Some reference has been made by hon. friends here but I would not make a comment on that at length. But I would like to submit, Sir, that for achieving these objectives we have been making different types of strategies, working out these strategies so that taking a realistic view of the situation, we are able to solve this problem. This is being done in a number of ways. Firstly, as the hon. House would recall, the National Development Council has approved the Document prepared by the Planning Commission called "An Approach to the Fifth Five Year Plan". If that Document is examined it would be seen that this objective of 100 per cent enrolment in the age group 6-11 and 75 per cent enrolment in the age group 11-14 must be achieved before the end of the Fifth Plan. It will also be observed by the hon. Members that out of the total outlay which has been provisionally proposed for the educational sector, half has been allotted for elementary education and elementary education has been included in what is called, the minimum national needs programme of the country. Therefore, the fear that has been expressed, that elementary education is not being given either the financial backing or the importance, will be, I hope, proved to be unfounded. And my Ministry will be sparing no effort in seeing that these targets about which a national consensus has already emerged are achieved because these targets have been accepted by the Education Ministers of all the State Governments and then in the National Development Council by the Chief Ministers of all State Governments. I do not think there is any difference of opinion that these are very important targets and we must implement them. Now, within this framework we have been evolving various types of strategies. We realised, for example, that there are economic factors, factors of poverty, factors of social backwardness which have prevented children in the past from being enrolled in schools or, having been enrolled in schools, made them drop out. Now, this may be partly due to the inadequacy of the schools, but more often it is due to social and economic factors. In order to overcome this we are working out a whole scheme of informal education, part-time education and whole-time education, where schools cannot be established. For example, in very small villages where there are only a few houses, it may not be possible to have a full-fledged school. We are devising various other methods to ensure that education reaches all these children. We have also put forward the concept of community schools which will act as models and which will, we hope, be multiplied as the general community sees the advantages in having schools of this type in which the parents get involved. Most of the parents are unfortunately still illiterate and, therefore the school's duty does not end merely with providing education to children. It should be also extended wherever possible, to the parents of the children. Then, there are various other types of

[Prof. S Nurul Hasan.]

community services which should be dovetailed into the school programme, so that we try and implement at least the fundamental concepts of Mahatmaji in respect of a national education programme For the young people in the age group 15 25 our strategy will be to involve them in three different types of activities. The first is informal education, literacy programme, functional literacy programme, improvement of skills whether these are handicraft skills, agricultural skills or industrial skills. The second is physical culture and education I am very glad that my hon friends have emphasised the need for sports. We are deeply conscious of the fact that physical culture and physical instruction is extremely important for the development of a healthy nation. Therefore, we want to involve the young people in this type of activity. The third and perhaps no less important than any of the other two activities is that the youth must be involved in constructive, nation-building activities and in social service For this purpose we have been working out a scheme for joint effort by the student youth and the non-student youth, so that the two can work and function together. I am grateful to my hon friend who paid a compliment to the Ministry of Education for the campaign organised this year of youth against famine. In spite of the fact that we have not achieved that measure of success which we would have liked to achieve, on the whole I think the results have been extremely encouraging. I am most grateful to all those teachers, students and people in the villages who have contributed to the success of this scheme. Sir, in this scheme there have been attempts and brave attempts when young people from colleges and universities have taken to constructive manual labour along with the people of the villages themselves. They tried to live and identify themselves with the people of the villages, so that the alienation of the student youth, which has been spoken about, disappeared to some extent Sir, I am extremely grateful to my friends for having repeatedly mentioned the character-building task and role of education. I am in full agreement with them that this is extremely important for us We have not only to inculcate a proper sense of values in the accepted national policies such as secularism, such as democratic way of life, such as socialism, such as abhorrence for such practises as untouchability, and a general humanising influence of education is absolutely vital. Along with this, I entirely agree that we have to remember the role of education in creating a healthy respect for our culture, for our basic values of culture. My friend, Mr. Tyagi, asked me to define what culture is I would not attempt to do so because as he undoubtedly knows, no two academics will have the same definition of culture. When I was a student doing a paper on medieval Indian culture, we realised that in the whole class no two students had the same concept or definition of culture So, I will not attempt to define it. But there are certain aspects of culture on which there can be no difference of opinion.

6 P.M.

SHRI O. P. TYAGI: But you can define Indian culture.

PROF. S NURUL HASAN. Therefore, the basic values of Indian culture which are well understood, those must be inculcated through the educational system Side by side with it, with our feet firmly planted in the mother earth of India, we must, as Gandhiji said, 'allow the fresh breeze to enter from whichever corner it comes." We must encourage a scientific outlook and prepare our people to use science and technology as a system of culture without being, as Gandhiji said, 'blown off their feet.' This is easier said than done. We are conscious that these are the objectives We are trying to bring about changes in the curricular, co-curricualr and extra-curricular activities in the schools. In fact, a working group of experts is trying to evolve prototypes of syllabus and of extracurricular and co curricular activities. We hope that these will meet with the approval of the State Governments and that they will be able to implement them

Sir, it has also been suggested by an hon Member that the Education Ministry has failed to have those text books removed from the curriculum which militate against the basic concept of secularism or national integration. Sir, I am deeply conscious of the failure of my Ministry

for which I accept the fullest responsibility because you, Sir, in this House and in the other House have given to the Ministers a great deal of authority to see that their policies can be implemented. But, Sir, this happens to be one of the areas in which our failure is not as marked as it is in many other spheres In the time of my distinguished predecessor, Prof. V. K. R. V. Rao, a working group was appointed to make a crash evaluation of the school textbooks in the most sensitive subjects. That work has been completed more or less. A very large number of textbooks were carefully examined. Some were found to be completely objectionable. Some were found to be partly objectionable while others were considered to be all right. The Education Ministry drew the attention of the State Governments to this report. I am very happy to submit, Sir, that in most cases the Education Ministries of the State Governments expressed their agreement with the comments that we had made and have promised that they would take the necessary action. In some cases action has already been taken. In other cases action is going to be taken. But we are confining our activities merely to pointing out the faults. We have also, through the National Council of Research and Training, set up groups which are preparing text books which, we hope, will satisfy the needs and urges of the people.

Sir, while I am on the subject of the textbooks I must express my horror at the textbook which my distinguished hon'ble friend, Shri Sanyal, mentioned here. I took the liberty of going out to the Lobby in order to have a good look at that book and I feel that Mr. Sanyal's words were perhaps not strong enough so far as that book is concerned. I will certainly do whatever lies in my power to see that that book and such other books are not inflicted on the Indian children.

Sir, I would like briefly to mention the question of sports before I go on to the question of the Aligarh Muslim University on which Dr. Ahmad has spoken. Sir, in the matter of sports we realise that the international competitions are held under the Olympic rules. Olympic rules provide that the organisation of sports shall be with voluntary organisations not controlled by Government. Therefore, when there is a lack of control from the Government, it becomes a little embarrassing for the Government to do much about what these voluntary organisations are doing. In the case of the Manager of the Indian Hockey Team for the World Cup I am conscious of the fact that many distinguished hockey players like Mr. Dhyan Chand, Mr. K. D. Singh 'Babu' have expressed their concern at the choice. So we have suggested to the All India Council of Sports, which is an expert body—which also has the other component of lay people but more than half of the members are experts—to hold discussions with the Indian Hockey Federation to see whether this matter can be settled in a mannner which will be generally satisfactory to the country.

Sir, I would like to take some of your time and that of the House for a discussion of the Aligarh Muslim University. Sir, I must start by making a confession. From my early boyhood I have looked upon Dr. Ahmad as a political friend, philosopher and guide and I have not yet, Sir, got rid of that basic feeling.

As this House will recall, I tried my best to act on the advice which many hon. friends, including Dr. Ahmad, gave before the Aligarh Muslim University Bill was brought before this House, and Dr. Ahmad was generous enough to make a reference to it. I would repeat that the suggestions which he has given are given and will be given the fullest and the most careful consideration by Government. Sir, I would like to make two or three points in this respect. Firstly, the main demand which is being put forward regarding the amendment of the Act has centred round one specific demand which, I am afraid, the Government will not be able to accept and which, I am afraid, Dr. Ahmad will not be able to accept either, and that is that the preamble of the Act should be so amended as to declare that the Aligarh Muslim University is an institution established and administered by the Muslim minority of India in terms of article 30 of the Constitution. Sir, when I placed this Bill for the consideration of the House, I explained the Government's point of

[Prof. Nurul Hasan.]

view at length, and except for probably one or two Members, there was general agreement that this demand could not be accepted. Therefore, I would like to make this point very clear. Now, if this point is made clear, then the question that arises is that, firstly, the country needs to be assured that the Aligarh Muslim University has a definite historical character and the Government will not and does not propose to alter that character. Sir, that assurance has been given repeatedly by the Prime Minister, by myself and by other members of the Government. I stated in the other House that the character of the University was defined in the original 1920 Act in the preamble. In section 4(1) of the Act, it is stated that the University will continue to perform the obligations of the Mohammedan Anglo-Oriental College. That has not been changed. Section 5(2) gave to the University a special responsibility of making provision for Islamic theology and learning.

That has not been altered. These sections remain in exactly the same form in which they were first enacted by the Central Legislature in 1920, and the Government have no intention of making any changes therein. Furthermore, as a result of the political campaigns that have been going on, it is being said that while the Government claims that this historical character has not been altered and will not be altered, it has been a reality that in the three basic policy-making bodies, the Court, the Academic Council and the Executive Council of the University, the Muslims have had, for historical and traditional reasons, a majority. Sir, we realise that the Muslims have had, for historical and traditional reasons, a majority, and the Government have no intention of bringing about changes so that this majority is artificially reduced to a minority That is not the policy or the intention of the Government.

Then, Sir, I come to the specific points which Dr. Ahmad has raised Firstly, he spoke of the internal administration of the University and made out the point that the Vice-Chancellor in Executive Council has become the supreme authority and the Central Government, through the Vice-Chancellor, overshadows the University.

Sir, I most respectfully beg to differ from the last part of it. No Vice-Chancellor, having been appointed, takes his orders from the Ministry of Education and, in fact, a Vice Chancellor who were to agree to take his orders from the Ministry of Education would not be a fit person to be appointed as a Vice-Chancellor. But, Sir, I would like to clarify the other point that has been made by Dr. Ahmad. He has feeling that in the appointment of the Deans and the Heads of Departments, the Vice-Chancellor will have a good deal of voice and, therefore, it creates an impression although, in my opinion, it is unjustified, that the principal authorities of the University are a nominated body. And, therefore, Sir, I am entirely in agreement with Dr. Ahmad that this system should be changed and the Dean and the Head should be either appointed on the basis of rotation or on some other objective criterion in which the subjective element of selection should not exist. Similarly, he made a reference to the Court and said that it had ceased to be the supreme governing body. Sir, unfortunately, I was not expecting this question to come up at such a length and, therefore, have not brought the documents with me, but I think I am quoting correctly. Sir, in the 1951 Act, the Court was declared to be the supreme governing body and was given the right to review the acts of the Executive and the Academic Council save where these Councils have acted in accordance with the powers given to them by the Act or the statutes. I think these are the precise words. Sir, if you examine the list of powers and functions given by the Act and the statutes to the Executive and the Academic Council, you would notice, Sir, that there is hardly anything of substance or significance to the functioning of the University which has been left out. Therefore, in no matter of significance could the Court review either the actions of the Executive Council or the actions of the Academic Council. Sir, in the Act which this House has been pleased to approve, it is stated that all important policy matters of the University can be reviewed by the Court. Sir, this, I would submit, is a point that perhaps has not been fully examined by my distinguished friend. Then, Sir, in regard to the Students' Council, he is

under the impression that the Students' Union has been bypassed. Sir, this again does not correspond to the facts. The President, the Vice-President and the Secretary of the Students' Union are the *ex-officio* members of the Court. But if an impression is going round that there is some attempt to have a nominated element—there is no nominated element—then, I am quite prepared to go along and say that the other members or at least half the members, apart from these office-bearers of the Union and a few other categories, should be directly elected by the student community so that there is no feeling that the student community is being bypassed. And I would like to make this submission that till now there is no other University where students have been given so much representation on the court. And the court is not a mere debating society. Five of the 21 members of the Executive Council will be elected by the Court. And I therefore feel that there has been a great deal of misunderstanding about the Act and the statutes. I hope that my honourable friends would try to clarify these points so that it does not lead to a hysteria being built up on the basis of misunderstanding. And I would repeat that many of the changes which have been suggested by Dr. Ahmad would be acceptable to the Government even in the matter of composition of the court, bringing in people representing Muslim culture and learning. We have an open mind on this. I have discussed this matter with the representatives of the staff association, and have indicated to the staff association that most of these demands and these matters are such on which the Government would be prepared to go along with the academic opinion and that I hope that the Executive Council would soon make the relevant changes in the statutes, and I will be quite prepared to advise the Visitor to accept those changes. I think that should meet most of the points which Dr. Ahmad has raised in this debate. I am most grateful to him for having done so. He has also referred to Jamia Milia and this matter has also been referred to by another honourable Member. There is no discrimination either for Jamia and against other institutions of higher learning or against Jamia and in favour of other institutions; either way there is no discrimination. The difference in figures which were given out of grants was on the basis of the number of teaching departments, the functions that the institutions have been performing and the total enrolement. All those factors have to be taken into account in fixing the normal grant. One of the aims and objects of Jamia has been to impart instruction through the medium of Urdu. This it has been doing and the Government has been giving as much assistance as is possible in accordance with the norms that have been laid down. While I would like Jamia to increase its research output in Urdu, I would submit that Urdu is a language, as you quite correctly pointed out, of India and not of that part of the country which is now Pakistan. Therefore, it is but natural that our own people should take a great deal of interest in Urdu. I hope that not only this institution, but many other Universities, will be taking a greater interest than they have been taking. They have been taking a great deal of interest in research work in Urdu and imparting higher education in Urdu. I am subject to correction, if my memory does not fail me, the total number of persons studying Urdu in the other Universities of Uttar Pradesh is larger than the number in the Aligarh Muslim University and Jamia Milia put together. I am subject to correction, but this is my impression. Recently the Banaras Hindu University has decided to establish a separate Urdu Department in Banaras. Therefore, the development of Urdu is a programme in which we are all interested and it is not an interest which is confined to a particular community.

While I am referring to the language issue, I would like to make a specific reference to what Shri Appan said. In regard to the medium of instruction at the elementary stage, Government accept fully and wish to implement the provision in the Constitution. Article 351A lays down:

"It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facili-

[Prof S Nurul Hasan]

ties for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic mino rity groups "

In accordance with this broad policy, the Government of India would like to provide all the necessary facilities and in the cases of Andaman and Nicobar, we are conscious of the fact that there is a Tamil speaking minority which has every right to have its children educated through the medium of Tamil and I hope a decision will be taken soon in this regard

Shri Appan is not here But I would like to say that while we want to give support to every language of India, the Government of India have a special obli gation under the Constitution in regard to Hindi and therefore you cannot blame us if we give far greater attention to the development and promotion of Hindi than to the other languages It is not that we hold other languages to be un important We consider them to be very, very important and we want to provide every facility for them to develop But, Sir, Article 351 of the Constitution lays down

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite cul ture of India and to secure its enrich ment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India spe cified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desir able, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages "

This is a Constitutional obligation of the Central Government and the Central Government would be failing in its duty if it did not consider that the develop ment of Hindi is one of the major tasks of the Ministry of Education

SHRI KRISHAN KANT Mav I put one small question to the hon Minister for Education? Gandhiji in his last days had emphasized and wanted to do one thing during his life time, namely, all the regional languages should have the Devnagari script This has been emphasized by Vinobaji also May I know whether the Government of India has considered this and if so what is their view on this?

PROF S NURUL HASAN We have provided facilities to all those who have tried to write various regional languages through Devnagari script But we feel this is a matter on which passions may be aroused and it may be considered to be an imposition We, therefore, want to pursue a policy which will endear Hindi to people who speak their languages rather than create suspicion in their minds that Hindi might ultimately dominate their own languages and may lead to the stultification of their own lan guages Therefore, the policy of the Government is that we will provide facilities and encouragement to all other Indian languages But we have a special duty in so far as Hindi is concerned

It has been emphasized by several hon Members that the educational policy deserves to be changed.

I have already stated that we are attempting to bring about a change in the content of education, in the technique of imparting education, in linking up education with the processes of production and the other processes of the com munity so that it becomes an integral part of the life of the community But, while we are dealing with this matter, I would submit, Sir, that we feel that equa lity of educational opportunity is not fully provided by us and it is an admis sion which I want to make straightaway If it had been possible for us, not only in terms of money, but also in terms of teachers and other resources, the inputs needed I would have liked to upgrade all the schools that we have in the country But, Sir, clearly I feel that this may not be possible within one Plan period We, are, therefore proposing—I hope that our proposal finds general acceptance—that we set up in each development block a community primary school which will

have its services of extension available to the entire block and to the other villages there and where 50% of the seats will necessarily be reserved for the weaker sections of the community in that block and where 25% of the total enrolement will be given to the poorer sections of the community which will be given full maintenance allowance so that the parents do not have to buy them other food or clothes or books and they can manage to go through this education in these schools and similarly at the district level we will have a comprehensive school which can again make its services available to all the higher secondary schools in the neighbourhood

Now, Sir, one school in a district or one school in a block is not adequate to bring about a major change by itself But we hope that this will be a nucleus so that other schools will start following its example and the new type of curriculum would be made available and the only merit of this curriculum and pattern would be that it would be uniform throughout the country If we are able to implement this scheme, I hope that some change would be noticeable even at the grass roots level of the most backward blocks and groups of villages in our country

Sir, this brings me to a problem which I must place before the honourable House Every one knows about it though not many friends have made a reference to it in very clear terms and that, Sir, is the question of financial allocations Most of our plans do require some money We have done our best to see that the cost is kept down to the minimum possible so that some impact can be felt all over the country in the countryside, particularly amongst the weaker sections of our society But whether in view of the present depressing economic situation we would be able to get adequate allocations, I do not know I hope we will be able to get it and if we are able to get it, then, Sir, I am personally optimistic that the targets which have been approved by the National Development Council and the strategy which has been followed by the Central Advisory Board of Education can be implemented

Sir, I very briefly refer to the question of social welfare I am sorry the hon. lady Member is not present But I would specifically like to draw the attention of the House to the new programme of integrated child care services, health care and looking after the mothers and providing pre school education to children up to six years of age We want to link it with the school system so that it will be possible for a child who has already been playing in, so to speak, the compound of the school from the age of 3 and who is being given pre school training of hand, of mind, of coordination of the senses, whose curiosity has been aroused, to go to the school when he reaches the age of six years when he would be mentally and emotionally prepared to be able to continue that education This scheme we consider to be extremely important For this, naturally we will need the help and support of voluntary agencies, and particularly the Central Social Welfare Board and the State Social Welfare Boards We would like to bring about certain organizational changes in the Social Welfare Boards so that they are able to reach the grass root level, village level For that, Mahila Mandals could be established which would be able to supplement the efforts which would be made at the Government level

AN HON MEMBER It will be dominated by upper class women

PROF S NURUL HASAN If it reaches the grass root level, my hon. friend, it will not be dominated by upper class women

Sir Shri M Asad Madani raised the question of recognition of degrees of Deoband I am quite prepared, Sir, to hold a discussion with him to go into the academic merits if he would be so kind as to discuss this matter with me

Regarding the monuments, mosques and Madarsa of Bharatpur and Alwar, my officers in the Archaeological Survey of India tell me that no mosque or Madarsa, either in Bharatpur or in Alwar, is under Central protection and, therefore, I do not think it would be right to blame the Archaeological Department for that

So far as the mosque in Kudsia Garden is concerned, we broadly accept the prin-

[Prof S Nurul Hasan]

ciple, and this is the Government's policy, that at the time of protection if an institution, if a monument, was under worship, then worship shall be permitted in that monument If at the time of protection, worship was not being carried out in monument, which is protected, then it would not be desirable to permit worship to be started there at any time after the protection has been granted Now, Sir, according to the information that is given to me, the list of protected monuments which was published in 1928, contains the following description This mosque shall not be used for religious purposes But Sir, if it can be proved that this information is incorrect, that in fact worship was going on in that mosque until 1947, Government would be prepared to consider this matter, because the policy is a clear policy that we do not want to stop worship in a monument where it was being carried out at the time of protection Another point which needs to be explained was raised by my friend, Shri Appan, who is always so kind and generous He said that merit scholarships are given irrespective of the means of the candidate Except the National Science Talent Scholarship, there is no other scholarship of the Government of India which is not a merit cum-means scholarship The National Science Talent Scholarship has a very specific purpose and the scholarship to Scheduled Tribes is also without any means test All the other scholarships of the Government of India, like the National Scholarship, National Loan Scholarship, National Scholarship for Study Abroad, etc , have a means test attached to them and the children of the well to do people are not eligible to receive these scholarships

Another point raised by Shri Appan was regarding the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students in various educational institutions Sir, my Ministry is in entire agreement with the hon Member that this should be implemented and in the institutions which are under the control of the Ministry, we are taking fairly energetic steps to see that this is being implemented This year, for example, the Council of Indian Institute of Technology took a decision that if the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates of the requisite ability were not available, then whosoever was available, would be taken and special remedial courses would be provided to them If the seats were not filled even then, then the seats would be kept vacant rather than satisfying ourselves that we had done our best I am told that the response has been very good this year I am going to review the position and if the response is not adequate, then the Institute will go to the potential candidates rather than merely asking the potential candidates to come to the Institute We sincerely believe that this constitutional obligation has to be implemented by us

Sir, the point that was raised by Shri Sitaram Singh is again depressing me. I have heard some other complaints also that in many of the village schools, the children and even the teachers belonging to the Schedulel Castes and Scheduled Tribes have not been treated well. I have been working on a proposal that in the code of conduct for teachers we must lay down specific guidelines that if any teacher is found to be guilty of practising untouchability or of ill-treating a Scheduled Castes or Scheduled Tribes student or a fellow teacher, then that would be one of the important grounds for dismissal of the teacher concerned As several Members have already pointed out, naturally the implementation of this policy will have to be with the State Government We are already trying to implement it in the Central Schools and in the Schools in the Union Territories The Delhi School Education Bill has been passed by us and the rules are being drafted. All these points being taken due note of.

The point raised by my hon friend, Shri Shyamlal Gupta, about the lack of progress insofar as the publication of books in regional languages is concerned, I would like to submit that insofar as I would like concerned, 2,000 titles have already been published or are in the Press That is to say, the work has been completed Either the publication has already taken place or it is being published Many of our South Indian languages have done even better compared to the number of persons involved in producing the books Therefore, Sir, I am optimistic though naturally I would like the progress to be more

On a point of personal explanation, I would like to say that I have not suggested to the Executive Council or the Academic Council of Delhi University that they may have a particular pattern of the managing committee of colleges I will apply my mind only when the amended statutes come to the Visitor for his approval, when I have to give my advice But till now I have not expressed my own personal opinion in the matter I think, Sir, you will agree with me that it would be unfair if I were to express my opinion before the University were to formulate its proposals

Sir, I have also been accused of pampering the teachers Sir, I plead guilty to it I pamper the teachers firstly because I myself belong to the same community and I am very proud to be a teacher It is only incidentally that I have been asked to do this work I have been a teacher, I hope I will go back to the profession and die as a teacher. I have no intention of giving up teaching But, Sir, the consideration that is being given to the teachers is not because they create a lot of trouble The consideration is being given to the teachers because they are the only people who teach How do you have education without someone teaching and if the teachers do not teach then what are you going to do? How are you going to carry on education? Is it through laws made by this august Parliament or the State Assemblies? Someone has to teach and if the teacher does not teach, who is going to teach? Therefore, Sir, teachers have to be given due consideration, due importance, as has rightly been pointed out in the National Policy Resolution on Education which was approved by this House in 1968 along with the other House

Sir, I would like finally to again express my gratitude to the hon Members for the interest they have taken in the work of the Ministry of Education, Social Welfare and Culture and I would beg my hon friends to forgive me because I have not been able to touch on every point that has been raised in the House because it is already quarter to seven.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) THE ANDHRA PRADESH APPROPRIATION (NO 2) BILL, 1973

(II) THE DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL, 1972

SECRETARY Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha —

(I)

In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Andhra Pradesh Appropriation (No 2) Bill, 1973 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 25th July, 1973

(2) The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill

(II)

I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on the 25th July, 1973 has adopted the following motion further extending the time for presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Disturbed Areas (Special Courts) Bill 1972 —

MOTION

That this House do further extend up to the first day of the last week of the next session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill to provide for the speedy trial of certain offences in certain areas and for matters connected therewith "

Sir, I lay a copy of the Andhra Pradesh Appropriation (No 2) Bill 1973 on the Table

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) The House stands adjourned till 11 o clock on Thursday, the 26th July 1973

The House adjourned at forty eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday the 26th July, 1973

MGIPCBE—S7—13 RSS/ND/73—11-2-74—595